गुजरात के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 204 | रायपुर | गुरूवार 17 जुलाई 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

झारखंड के बोकारो में एनकाउंटर, 25 लाख के इनामी समेत दो नक्सली ढेर; सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद

अरुणाचल प्रदेश में बिना परमिट के रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई

अरुणाचल (एजेंसी)। बिना वैध इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के रहने और काम करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। राजधानी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं और आईएलपी के बिना राज्य में रह रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। नाहरलागुन-ईटानगर कैपिटल रीजन के एसपी नीलम नेगा ने बताया कि यह अभियान बंदरदेवा, कारसिंगा, नाहरलागुन टाउन और पापू हिल्स जैसे इलाकों में चलाया गया।

मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

धन–धान्य कृषि योजना से किसानों की बढ़ेगी आमदनी

नई दिल्ली. एजेंसी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक 16 जुलाई बुधवार को हुई, जिसमें खेती और हरित ऊर्जा से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं.

नई कृषि योजना- पीएम धन-धान्य कृषि योजना

सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है. इसका

मकसद देशभर के कृषि आधारित जिलों का समग्र विकास करना है. इस योजना के अंतर्गत 36 विभिन्न कृषि योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा. इस योजना का वार्षिक बजट 24 हजार करोड़ रुपए है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में सहायक होगी.

एनटीपीसी को मिलेगा ग्रीन एनर्जी निवेश का समर्थन - सरकार ने ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी को 20,000 करोड़ तक की मदद देने की मंजूरी दी है ताकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी (ग्रीन एनर्जी) में तेज़ी से निवेश कर सके. **एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी समर्थन** - ऊर्जा क्षेत्र की एक और प्रमुख कंपनी एनएलसीआईएल को 7,000 करोड़ रुपए का समर्थन मिलेगा।

अब 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद मॉनसून सत्र

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में कुल 8 नए विधेयक पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर अब 21 अगस्त तक चलेगा। पहले संसद 12 अगस्त तक ही चलने वाली थी, जिसे बाद में एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोई बैठक नहीं होगी। लोकसभा सचिवालय ने जिन प्रमुख विधेयकों की जानकारी दी है उनमें टैक्स, शिक्षा, खेल, और खनिज नीति जैसे क्षेत्रों से जुड़े विधेयक

शामिल हैं।

लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक, 2025, खनिज और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (संशोधन), 2025 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इनके अलावा, गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में पुनः प्रतिनिधित्व निर्धारण विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 और आयकर विधेयक, 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।

संसद की विधायी शाखा के अनुसार, इस बार सभी सांसदों को 'मेंबर्स पोर्टल' के माध्यम से ही समन और सूचनाएं भेजी गई हैं।

गुरुग्राम को 188 करोड़ की विकास सौगात, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन

गुरुग्राम एजेंसी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में जिला के विकास के लिए 188 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

पटौदी विधानसभा में सड़कों का हुआ उद्घाटन जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे लोक निर्माण विश्रामगृह में पहुंचे। जहां उन्होंने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ 5 लाख 67 हजार की लागत से बनाए गए पचगांव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर डबल लेन मार्ग तथा 13 करोड़ 18

लाख 83 हजार रुपए की लागत से हेलीमंडी, फर्रुखनगर वाया मेहचाना मार्ग के नवीनीकरण का उद्घाटन किया।

सोहना विधानसभा क्षेत्र को मिली यह सौगातें मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए की लागत से निर्मित जीए रोड से अलीपुर हरिया हेड़ा मार्ग तथा रायसीना गांव में बने मंदिर रोड का उद्घाटन किया।

पाकिस्तान सीमा पर गरजेगा 'हवाई टैंक', इस हफ्ते यूएस से भारत आ रही अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप

नई दिल्ली एजेंसी। भारतीय सेना की मारक क्षमता में इस सप्ताह एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अमेरिका से बहुप्रतीक्षित अपाचे AH-64E अटैक हेलिकॉप्टरों की पहली खेप इसी हफ्ते भारत पहुँच रही है। पहली खेप के तहत तीन हेलिकॉप्टर मिलेंगे, जिन्हें रात के अंधेरे में भी दुश्मनों को खोजकर तबाह करने की उनकी काबिलियत के लिए जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार, इन 'फ्लाइंग टैंक्स' कहे जाने वाले हेलिकॉप्टरों को पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। हेलिकॉप्टरों की लैंडिंग गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होगी, जिसके बाद इन्हें सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा।

भारतीय सेना ने इन हेलिकॉप्टरों के लिए पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। जोधपुर में करीब 15 महीने पहले ही इनके लिए एक अलग बेड़ा तैयार कर लिया गया था। हालांकि, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अन्य कारणों से इनकी डिलीवरी में लगातार देरी हो रही थी। यह डिलीवरी भारत और अमेरिका के बीच 2020 में हुए छह अपाचे हेलिकॉप्टरों के सौदे का हिस्सा है। पहले यह खेप मई-जून 2024 में मिलनी थी।

यह सेना के लिए खरीदे गए अपाचे हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना के लिए 2015 में 22 अपाचे हेलिकॉप्टरों का सौदा हुआ था, जिनकी डिलीवरी 2020 में पूरी हो चुकी है। वायुसेना की दो अपाचे स्क्वाड्रन पहले से ही पठानकोट और जोरहाट में सक्रिय हैं।

तेजस मार्क-1 ए के लिए मिला इंजन, वायुसेना को मिलेंगे नए फाइटर जेट

भारतीय फाइटर जेट तेजस मार्क-1ए के निर्माण में अब तेजी आएगी। इस लड़ाकू विमान के लिए अमेरिकी कंपनी ने भारत को जेट इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस मार्क-1ए के लिए सोमवार को भारत को जीई-404 इंजन प्राप्त हुआ। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह अमेरिकी कंपनी से मिला दूसरा जेट इंजन है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय विमानन कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) तेजस का निर्माण कर रही है।

सरकार का ध्यान टियर 2 और टियर 3 शहरों के उद्यमियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित : पीयूष गोयल

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मजबूत किया है। साथ ही, समावेशी प्रयासों और भारत की उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने की प्रतिबद्धता के माध्यम से विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के उद्यमियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल (एनएसएसी) की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करने के लिए इनोवेशन को आधार के रूप में रेखांकित किया, जिसमें आरएंडडी और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

विदेशों पर निर्भर न होकर भारत को अपनी तकनीक पर देना होगा ध्यान

अनिल चौहान ने बताया क्या है सेना की जरूरत

नई दिल्ली एजेंसी - चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने हाल के संघर्षों में ड्रोन की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि ये छोटे-छोटे हथियार जंग में पासा पलट सकते हैं। मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया है कि हमारे भूभाग और हमारी जरूरतों के लिए निर्मित स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणालियां (UAs) और सी-यूएएस क्यों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन

सिंदूर के दौरान बिना हथियार वाले ड्रोन और लॉइटर मुनिशन का इस्तेमाल किया, मगर भारतीय सेना ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया। जनरल चौहान ने यह भी चेतावनी दी कि विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी ताकत को कमजोर कर सकती है। उन्होंने कहा कि आज की जंग को कल की तकनीक से नहीं जीता जा सकता। ड्रोन और नई तकनीक अब युद्ध के मैदान में सबसे अहम हथियार बन चुके हैं। उनकी इस बात ने साफ कर दिया कि भारत को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीक पर ध्यान देना होगा।

देश | घाटी में रोजगार

दक्षिण कश्मीर में सेना की पहल, गोलियों की जगह गूंज रही सिलाई मशीनों की आवाज

नई दिल्ली एजेंसी। जहां आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हजारों घर उजाड़े, वहीं भारतीय सेना यहां लोगों के घर बसाने व घर चलाने के लिए उन्हें कुछ प्रशिक्षण दे रही है। खास तौर पर सेना ने दक्षिण कश्मीर में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है।

सेना की मदद से यहां दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया गया है। बालापोर का यह सेंटर एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। यही कारण है कि अब कश्मीर के इस इलाके में गोलियों का शोर कम और सिलाई मशीन की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी है और इस परिवर्तन का बड़ा श्रेय भारतीय सेना के

प्रयासों को जाता है।

सेना के इन्हीं प्रयासों की बदौलत आज दक्षिण कश्मीर की कई महिलाएं 20 हजार रुपए तक की कमाई अपने इस प्रशिक्षण के बूते कर रही हैं। इससे यहां रहने वाली महिलाओं के जीवन में स्वालंबन तो आया ही है, साथ ही सेना को लेकर भी उनके दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। न केवल यहां रहने वाली सैकड़ों महिलाएं, बल्कि उनके परिवारजन भी अब सेना को एक सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। इस अभियान से जुड़ने वाली महिलाओं का कहना है कि वे अपने और अपने परिवार की जीवनयापन का खर्च उठाने में सक्षम हुई हैं। इससे उनके परिवार को एक नई राह मिली है।

भारतीय सेना के मुताबिक यह एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर 22 जुलाई 2020 को प्रोजेक्ट सद्भावना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह 15 फरवरी 2021 से तोहा फाउंडेशन द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो बालापोर का यह सेंटर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है।

जयशंकर ने चीन के सामने पाकिस्तान आतंकवाद पर चेताया

एससीओ समिट में भारत का कड़ा संदेश

बीजिंग , एजेंसी

चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शिखर बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान को लताड़ते हुए जयशंकर ने चीन को भी अप्रत्यक्ष रूप से चेताया कि आतंकी ताकतों को समर्थन देना किसी के हित में नहीं है।

जयशंकर की दो टूक बातों पर बदला पाकिस्तान का सुर भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का रुख नरम

पड़ता नजर आया। उन्होंने बैठक में कहा कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का पक्षधर है। वहीं जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की ओर से की गई 'ऑपरेशन सिंदूर' की कार्रवाई पूरी तरह उचित थी।

बीआरआई पर भी जताई आपत्ति, चीन पर परोक्ष हमला

जयशंकर ने अपने संबोधन में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने ज़ोर दिया कि कोई भी बहुपक्षीय सहयोग परस्पर सम्मान, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत लगातार चीन की इस परियोजना का विरोध करता रहा है, खासकर इसके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने को लेकर।

'आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं', SCO से सख्त रुख अपनाने की अपील

जयशंकर ने कहा कि स्ष्ह्ह की स्थापना का उद्देश्य आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी तीन प्रमुख बुराइयों से लड़ना था। ऐसे में संगठन को अपने मूल उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मकसद जम्मू-कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और धार्मिक विभाजन फैलाना था। उन्होंने कहा कि यदि भारत पर इस तरह के हमले दोहराए गए, तो जवाब में भविष्य में भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इस हमले की कड़ी निंदा का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों को न्याय के कठघरे में लाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर लगेंगे सख्त प्रतिबंध, नाटो ने दी चेतावनी

वाशिंगटन नाटो महासचिव मार्क रूट ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर भारत, चीन और ब्राज़ील को सख्त चेतावनी दी है। रूट ने बुधवार को कहा कि अगर ये देश रूस से व्यापार नहीं रोकते तो उन पर कड़े और सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटरों से मुलाकात के बाद यह बयान दिया।

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने की नई घोषणा की है और रूस के निर्यात खरीदने वालों पर 100त्न द्वितीयक टैरिफ लगाने की धमकी दी है, अगर अगले 50 दिनों में शांति समझौता नहीं होता है। मार्क रूट ने कहा, अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राज़ील में हैं, तो यह चेतावनी आपके लिए है। व्लादिमीर

पुतिन को फोन कर शांति वार्ता में सहयोग करें, वरना गंभीर असर झेलना पड़ेगा। सीनेटर थॉम टिलिस ने ट्रंप की योजना की सराहना की, लेकिन 50 दिन की समय-सीमा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुतिन इस अवधि का फायदा उठाकर युद्ध में ज़्यादा जमीन कब्ज़ा कर सकते हैं। रूट ने यह भी कहा कि यूरोप यूक्रेन को बेहतर स्थिति में लाने के लिए आर्थिक मदद देगा और अमेरिका बड़े पैमाने पर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराएगा, जिसमें हवाई रक्षा, मिसाइलें और यूरोपीय देशों द्वारा फंड की गई सहायता शामिल है।

शिक्षा में सहभागिता को बढ़ावा : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू होगा पालक–शिक्षक संवाद अभियान

पालक और शिक्षक मिलकर संवारेंगे बच्चों का भविष्य – वर्ष में तीन बार अनिवार्य बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के दौरान वर्ष में तीन बार पालक-शिक्षक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पहली बैठक अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी, जबकि द्वितीय एवं तृतीय बैठकें तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के 10 दिवस के भीतर संपन्न होंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि प्रत्येक जिले में इन बैठकों के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी विद्यालयों में यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से लागू हो।पालक-शिक्षक बैठकें न केवल शैक्षणिक संवाद का मंच होंगी, बल्कि वे बच्चों की संपूर्ण प्रगति पर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर भी देंगी। इन बैठकों के माध्यम से पालकों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी हो, परीक्षा के तनाव से कैसे निपटना है, और संवाद की आदत कैसे विकसित करनी है। साथ ही, 'बस्ता रहित शनिवार' जैसी पहल पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा जिससे बच्चे मानसिक रूप से हल्का महसूस करें और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। बैठकों के दौरान पालकों को बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के उपायों पर भी जानकारी दी जाएगी। विशेष रूप से उन्हें यह समझाया जाएगा कि बच्चों को खुलकर बोलने के लिए अवसर प्रदान करना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना, और जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आयोजित शिविरों में बच्चों को शामिल करना कितनी महत्वपूर्ण पहल है। इसके अतिरिक्त 'न्योता भोजन' जैसी सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भी पालकों को प्रेरित किया जाएगा।

इस पहल में डिजिटल शिक्षा को भी विशेष स्थान दिया गया है। बैठक के दौरान पालकों को दीक्षा ऐप, ई-जादुई पिटारा, डिजिटल लाइब्रेरी जैसे संसाधनों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे घर पर भी अपने बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षण सामग्री से जोड़ सकें। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में रोचकता बढ़ेगी, बल्कि पालक स्वयं भी शिक्षा के सक्रिय सहभागी बन सकेंगे।स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाली पहली पालक-शिक्षक बैठक को प्रत्येक स्कूल में भव्य, सुव्यवस्थित और संवाद-प्रधान रूप से संपन्न किया जाएगा। तदनुसार, तिमाही एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद होने वाली द्वितीय और तृतीय बैठकें भी सुनियोजित ढंग से कराई जाएंगी। इन बैठकों में बच्चों की अकादमिक प्रगति, पाठ्येतर गतिविधियों, स्वास्थ्य, और सामाजिक व्यवहार के संबंध में पालकों को अवगत कराते हुए, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की जाएगी—ताकि स्कूल और परिवार मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में कार्य कर सकें।

कलेक्टर ने अटल परिसर के निर्माण कार्य का अवलोकन किया

गुणवत्ता को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की

कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए

जशपुर । कलेक्टररोहित व्यास ने सोमवार को जिला संग्रहालय परिसर के पास बन रहे अटल परिसर के निर्माण कार्य का अवलोकन किया और गुणवत्ता को लेकर नगर पालिका अधिकारी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्य एजेंसी को कड़ी हिदायत देते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रीअटल बिहारी वाजपेयी की 100 वीं जयंती पर नगरीय निकाय और नगर पंचायत में अटल परिसर बनाने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में जशपुर में भी बनाया जा रहा है। अटल परिसर राज्य के सभी नगर निगम,नगर पालिका, नगर पंचायत में बनाया जाएगा।

कलेक्टर ने जशपुर में बन रहे मिनी इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया

उन्होंने कार्य एजेंसी को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में स्टेडियम का निर्माण कार्य चालू इसके लिए खेल विशेषज्ञों को स्टेडियम का अवलोकन कराए ताकि खिलाड़ियों को खेल संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ीयों को बास्केटबॉल, शतरंज,कैरम, टेबल टेनिस सहित अन्य खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला आयोजित

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिदृ2020 के पुनः उन्मुखीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक पाठ्यक्रमों में एनईपी के एक वर्ष के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों पर विचार करना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कहा कि एनईपी 2020 न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, बल्कि यह युवाओं को उनकी स्थानीय परंपरा और ज्ञान से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर देगी, जिससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

प्रथम तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ह्श्वक्क) डॉ. डी.के. श्रीवास्तव ने नीति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनईपी बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एक समग्र और लचीला शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है।द्वितीय तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के संयुक्त संचालक डॉ. जी.ए. घनश्याम ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत दर्शन पर विचार रखते हुए कहा कि यह नीति

आधुनिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को भारत की समृद्ध चिंतन परंपरा और नैतिक मूल्यों से जोड़ना एनईपी का अहम लक्ष्य है, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा ने एनईपी को वर्तमान और भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल और बाज़ार योग्यताओं से छात्रों को लैस करना है।कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एनईपी संयोजक श्री पंकज नयन पाण्डेय ने एनईपी 2020 पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बीते एक वर्ष में पाठ्यक्रम संरचना और वैकल्पिक विषयों के क्रियान्वयन के तहत अनेक प्रभावी पहल की गई हैं, जिससे

चिंगरापगार वाटरफॉल की खूबसूरती के बीच दिखी लापरवाही

गरियाबंद । जिले में लगातार हो रही बारिश ने चिंगरापगार वाटरफॉल की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। यह प्राकृतिक दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन रोमांच और मौज-मस्ती के चक्कर में कुछ लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। रविवार को ऐसी ही एक खतरनाक घटना सामने आई जब एक युवक पेड़ की जटाओं का सहारा लेकर वाटरफॉल के नीचे उतरने की कोशिश करता दिखा। नीचे की चट्टानों पर पानी के कारण काफी फिसलन थी, जिससे यह प्रयास बेहद जोखिमभरा साबित हो सकता था। न केवल उस युवक के लिए, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों के लिए भी यह एक गंभीर खतरा था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक को पेड़ की जटा से लटके हुए देखा जा सकता है। वह जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करता है, उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह देख वहां मौजूद अन्य लोग भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी की निगाहें उस पर टिकी रहती हैं, क्योंकि नीचे की फिसलन भरी चट्टानों पर किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद वाटरफॉल क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि वह पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए।

सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर । आईटी एक्ट की धारा 67बी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत दर्ज मामले में सरकंडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

साइबर टीप लाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकरजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए थाना सरकंडा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई।

गिरफ्तार आरोपी:

नाम- मुकेश कुमार माधवानी उर्फ मुक्कू, पिता- भीखमदास माधवानी

उम्रः 42 वर्ष

निवासीः अशोक नगर, महामाया आई.टी.आई के पास, सरकंडा, जिला बिलासपुर

क्या है मामला:

जांच के दौरान मोबाइल टावर लोकेशन,

आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर यह सामने आया कि आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से महिलाओं और बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन:

यह कार्रवाई अति. पुलिस अधीक्षक (शहर)राजेन्द्र जायसवाल एवं सीएसपी सरकंडासिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई।

गिरफ्तारी एवं आगे की कार्रवाईः

आरोपी मुकेश को 12 जुलाई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

गौ–तस्करी मामाले में फरार आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए गौ-तस्करी के एक फरार आरोपी मनसूर खान को गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आरोपी पिछले साल अगस्त 2024 में लोदाम थाना क्षेत्र के साईंटांगरटोली में हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया था।

क्या है मामला?

7 अगस्त 2024 को थाना लोदाम क्षेत्र में भारी मात्रा में चल रही गौ-तस्करी की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए साईंटांगरटोली में घेराबंदी की थी। इस दौरान 32 गौ-वंश के साथ 09 पिकअप वाहन, 04 कारें और 05 मोटरसाइकिल जब्त की गई थीं। मौके से 10 तस्कर पकड़े गए थे, जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए थे।

गिरफ्तार आरोपी की जानकारीः

नामः मनसूर खान, उम्रः 24 वर्ष, निवासीः बरगीडांड़, थाना रायडीह, जिला गुमला (झारखंड) आरोपी के खिलाफथाना लोदाम में अपराध क्रमांक 42/2024 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत मामला दर्ज है।

जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी मनसूर खान अपने घर आया हुआ है। तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह घटना में शामिल था। 13 जुलाई 2025 को उसे विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

पूर्व में गिरफ्तार अन्य आरोपीः

इस मामले में पूर्व में जुनैद आलम, सुहैल खान और चरकू उर्फ सरफराज को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस की कार्रवाई में योगदानः

इस कार्रवाई में निरीक्षक हर्षवर्धन चैरासे, प्र.आर. कृपा सिंधु तिग्गा, आर. हेमंत कुजूर और आर. सुभाष तिर्की की विशेष भूमिका रही।

एसएसपी का बयानः

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा, गौ-तस्करी के मामले में फरार आरोपी मनसूर खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसके अन्य साथी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गौ-तस्करी के विरुद्ध हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा।

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में हंगामा

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में हंगामा

0 कांग्रेस ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ठ होकर किया बहिर्गमन

रायपुर,। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जल जीवन मिशन में निर्धारित लक्ष्य से कम काम तथा अनियमितता को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए प्रश्न का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरूण साव द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर सदन का बहिर्गमन कर दिया।

विधानसभा के मानसून सत्र में आज कांग्रेस के भूपेश बघेल

ने जल जीवन मिशन में हुए अनियमितता का मामला सदन में उठाया। लोक स्वास्थ्य मंत्री अरूण साव ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में फर्जी काम हुआ था। 35 लाख घरों में कनेक्शन देने का वादा किया था लेकिन सिर्फ 15 लाख घरों में कनेक्शन दिया गया। कांग्रेस शासन काल में फर्जी जल टंकियां बनाई गई जिसके कारण मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य छग के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ एवं पेयजल उपलब्ध कराना है।

भूपेशबघेल ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में निर्धारित लक्ष्य से कम काम किया गया है। भारसाधक मंत्री अरूण साव ने कहा कि भूपेश बघेल का यह आरोप निराधार है। अरूण साव ने आगे कहा कि हमने जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण किया गया है। फर्जी आकड़े कांग्रेस शासन काल में दिये गये थे। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नोकझोंक हुई।

कांग्रेस के भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न के माध्यम से जलजीवन मिशन में हुए कम खर्च का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अनुमानित खर्च जितना था उतना नहीं हो पाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री इसको लेकर बार बार सरकार का मतंव्य स्वस्थ करते रहे।

अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपियों को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरी। मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 13.07.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गनियारी वर्मा मोहल्ला में आरोपीगणों के द्वारा अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब को बिक्री कर रहा है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम गनियारी वर्मा मोहल्ला में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपिया सोनिया वर्मा पति नवरतन वर्मा उम्र 40 वर्ष के कब्जे से कुल 22 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 1 नग गैस सिलेंडर, 3 गंज एवं मिट्टी का बर्तन को जप्त किया गया है तथा आरोपी प्रियांशु वर्मा पिता प्रमोद वर्मा उम्र 18 वर्ष 09 माह के कब्जे से कुल 30 लीटर महुआ शराब एवं 01नग गैस सिलेंडर, मिट्टी के बर्तन को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंग नवरंग, सहायक उप निरीक्षक गोपाल प्रसाद खांडेकर, सहायक उप निरीक्षक शिव कुमार साहू, प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव , प्रधान आरक्षक सनत पटेल, प्रधान आरक्षक 41 रवींद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक 938 घनश्याम आडिल, आरक्षक 421 नंद झरोखा सुमन, आरक्षक 902 रवि राजपूत, आरक्षक 252 जलेश्वर साहू, आरक्षक 212 प्रफुल्ल यादव महिला आरक्षक 933 दीपिका लोनिया का विशेष भूमिका रही।

सावन के पहले सोमवार पर देवबलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

भिलाई। भिलाई सावन के पहले सोमवार को अंचल के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। खासकर देवबलौदा गांव के नवरंग मंडप शैली में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों की सुबह से ही लंबी कतार लगी रही। यह मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है और सावन के दौरान यहां आस्था का खास केंद्र बन जाता है।यह मंदिर 13वीं शताब्दी में कल्चुरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था और यह भिलाई-तीन चरौदा रेलवे लाइन के किनारे, राजधानी और दुर्ग के बीच स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग तीन फीट नीचे स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर मौजूद कुंड को लेकर कई लोक कथाएँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगे शिल्पी ने इसे अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए इसका गुंबद बन नहीं पाया। मंदिर के कुंड के भीतर एक गुप्त मार्ग भी बताया जाता है, जो आरंग तक जाता है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक और दिलचस्प कथा है कि जब यह मंदिर बनाया जा रहा था, तब लगभग छह महीने तक लगातार रात का ही माहौल था, हालांकि खगोलशास्त्र के इतिहास में ऐसी घटना दर्ज नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में काफी समय लगा होगा, और उस अवधि को लोककथाओं में 'छमासी रात' के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार, मंदिर का शिल्पकार अपने काम में इतना मग्न हो गया था कि वह अपने कपड़ों तक को भूल गया और नग्न अवस्था में दिन-रात निर्माण कार्य करता रहा। इस समर्पण की कथा मंदिर की विशेषता को और बढ़ा देती है।

श्याम मंदिर में चोरी, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ

रायगढ़ । शहर के प्रसिद्धश्याम मंदिर में सोमवार की सुबह एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर घुसते हुए बाबा श्याम की मूर्ति पर चढ़ा कीमती हार और दो दानपेटियों से नकदी चुरा ली। चोरी गए सामान की कुल कीमत 10 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है। सूचना के अनुसार, सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर पता चला कि बाबा श्याम का सोने का हार गायब है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई जा रही है। साथ ही दानपेटियों से करीब 2 लाख रुपये नकद भी चोरी हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वायड की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है और चोरों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

रजत जयंती वर्ष में सांस्कृतिक चेतना को नई उड़ान: 'श्री रामलला दर्शन योजना' अंतर्गत रायपुर से विशेष ट्रेन हुई रवाना

रजत जयंती वर्ष में सांस्कृतिक चेतना को नई उड़ान: 'श्री रामलला दर्शन योजना' अंतर्गत रायपुर से विशेष ट्रेन हुई रवाना

श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत रायपुर से 850 श्रद्धालुओं का तीर्थयात्रा हेतु प्रस्थान – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं

रायपुर। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत रायपुर से 850 श्रद्धालुओं का तीर्थयात्रा हेतु प्रस्थान – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएंश्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत रायपुर से 850 श्रद्धालुओं का तीर्थयात्रा हेतु प्रस्थान – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप देने हेतु प्रारंभ की गई 'श्री रामलला दर्शन योजना' के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस पवित्र यात्रा के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनकी यात्रा के मंगलमयी होने की कामना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रद्धालुओं को हमारे 'भांचा राम' – श्रीरामलला के निःशुल्क दर्शन कराने की यह पुण्य यात्रा अनवरत जारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को साकार कर रही है, जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभु श्रीराम के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था।उन्होंने कहा कि ÷श्री रामलला दर्शन योजना÷ के अंतर्गत सरकार ने मार्च 2024 तक 20,000 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया था, किंतु प्रदेशवासियों की अद्वितीय आस्था, उत्साह, और सरकार की प्रतिबद्धता के चलते यह संख्या 22,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए ?36 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक बीते डेढ़ वर्षों में 27 विशेष ट्रेनें छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हो चुकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला तीर्थ दर्शन योजना केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग एवं वंचित वर्ग, अपने जीवन में एक बार प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान के दर्शन कर सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रारंभ की गई 'श्री रामलला दर्शन योजना' आज प्रदेशवासियों के जनजीवन से गहराई से जुड़ चुकी है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन आज रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने दोपहर 1:00 बजे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन के प्रस्थान के दौरान रायपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7 जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। तीर्थयात्रियों और उनके परिजनों में विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला।

रामानुजगंज में 19 जुलाई को होगा केसरवानी वैश्य समाज का सामाजिक सम्मेलन और सावन उत्सव

बलरामपुर । रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 9 स्थित लरंगसाय कम्युनिटी हॉल में 19 जुलाई को केसरवानी वैश्य सभा द्वारा भव्य सामाजिक सम्मेलन एवं सावन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारी को लेकर एक विशेष बैठक नगर के प्राचीन राम मंदिर परिसर में केसरवानी वैश्य सभा के अध्यक्ष वेद प्रकाश केसरी और सचिव सत्य प्रकाश केसरी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में देवेंद्र केशरी, जितेश केशरी, केसरवानी महिला सभा और केसरवानी तरुण सभा के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

बैठक का शुभारंभ महर्षि कश्यप के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज के सक्रिय सदस्य आलोक केसरी ने कहा कि यह आयोजन समाज को एकजुट करने और आपसी समन्वय को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं, जितेश केसरी, रूपेश केसरी, संतोष केसरी और मितेश केसरी सहित अन्य सदस्यों ने अपील की कि समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें।

केसरवानी तरुण सभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश केसरी और सचिव नयन केसरी ने जानकारी दी कि सम्मेलन एवं सावन उत्सव के दौरान बौद्धिक, सांस्कृतिक और खेलकूद से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनके लिए पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। महिला सभा की अध्यक्ष शोभा गुप्ता और सचिव प्रियंका केसरी ने कहा कि इस आयोजन में महिलाओं की भी विशेष सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक का सफल संचालन सत्य प्रकाश केसरी ने किया और आभार प्रदर्शन प्रियंका केसरी ने किया। बैठक में दिलीप केसरी, भारत लाल केसरी, योगेश केसरी, एकता केसरी, शीतल केसरी, रिंकी केसरी, अल्पना केसरी, गीता केसरी, पूनम केसरी, उषा देवी, आरती केसरी, शालिनी केसरी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम में केसरवानी समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष रमा सुशील केसरवानी सहित अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी भाग लेंगे। पूरे रामानुजगंज और जिले भर से समाज के लोग बड़ी संख्या में इस

महंत कॉलेज में TC शुल्क वसूली का NSUI ने किया विरोध

रायपूर संवाददाता। जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के निर्देशानुसार एवं जिला महासचिव दिव्यांश श्रीवास्तव के नेतृत्व में महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) निकालने पर लिए जा रहे ?300 अवैध शुल्क का विरोध किया गया।
जिला महासचिव दिव्यांश श्रीवास्तव का स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार छात्रों से मनमाने ढंग से शुल्क वसूलना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। एनएसयूआई ने महाविद्यालय प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में यह अवैध शुल्क पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया, तो उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। ज्ञापन देने के दौरान प्रशांत चंद्राकर, शिवांक सिंह, रिजवान खान, कृष सहारे, संदीप विश्वकर्मा, लेमन सोनवानी एवं सुमीत शुक्ला उपस्थित थे।

सेल ने घोषित किए सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता–2025 के नतीजे

सेल की खुशहाली लाने की संस्कृति को प्रतिभागियों ने खूबसूरती से पिरोया

देश भर से लगभग 1,000 कहानियां प्राप्त हुईं

महिला प्रतिभागियों ने जीते टॉप अवार्ड: 10 में से 8 खिताब किए अपने नाम

लोकशक्ति

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादक और महारत्न कंपनी ने स्व्वत्नश्1 के साथ मिलकर, आज राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता ड्ड 2025 के परिणाम की घोषणा की। ÷सेल: खुशियों की संस्कृति का निर्माण, जहां हर मुस्कान मायने रखती है÷ विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता को पूरे देश से जबरदस्त भागीदारी मिली, जिसमें लगभग 1,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। यह प्रतियोगिता उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफल रही। इसने दिखाया कि लोग सेल की विरासत और देश की तरक्की के साथ-साथ, लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लाने में उसके योगदान से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। जो कहानियाँ मिलीं, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि कैसे सेल ने पूरे देश में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया और खुशहाली फैलाई।
सेल कहानी लेखन डायमंड अवार्ड - हिंदी श्रेणी की विजेता का खिताब लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सुश्री कीर्ति सिंह के नाम रहा तो सेल कहानी लेखन डायमंड अवार्ड - अंग्रेजी श्रेणी का खिताब बेंगलुरु, कर्नाटक से सुश्री चंचला बोरा ने अपने नाम किया। पुरस्कार विजेताओं की विस्तृत सूची पुरस्कारों के साथ इस प्रकार है:

हिंदी श्रेणी

नाम	स्थान	पुरस्कार
सुश्री कीर्ति सिंह	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	डायमंड अवार्ड (₹10,000 और प्रमाणपत्र)
सुश्री प्रविन्ता कुमारी लामा	रांची, झारखंड	गोल्ड अवार्ड (₹7,500 और प्रमाणपत्र)
सुश्री नीतू कुमारी	बर्नपुर, पश्चिम बंगाल	सिल्वर अवार्ड (₹5,000 और प्रमाणपत्र)
श्री सौरभ मिश्रा	भिलाई, छत्तीसगढ़	कांस्य अवार्ड (₹2,500 और प्रमाणपत्र)
सुश्री हेमा कुमारी थयाल	राउरकेला, ओडिशा	सांत्वना पुरस्कार (स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र)

अंग्रेजी श्रेणी

नाम	स्थान	पुरस्कार
सुश्री चंचला बोरा	बेंगलुरु, कर्नाटक	डायमंड अवार्ड (₹10,000 और प्रमाणपत्र)
सुश्री उषा जे	भद्रावती, कर्नाटक	गोल्ड अवार्ड (₹7,500 और प्रमाणपत्र)
श्री टी. अविनाश	हैदराबाद, तेलंगाना	सिल्वर अवार्ड (₹5,000 और प्रमाणपत्र)
सुश्री प्रिया मंडल	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	कांस्य अवार्ड (₹2,500 और प्रमाणपत्र)
सुश्री स्नेहल पवार	नवी मुंबई, महाराष्ट्र	सांत्वना पुरस्कार (स्मृति चिन्ह और प्रमाणपत्र)

SAIL कहानी लेखन प्रतियोगिता-2025 के विजेताओं को हिंदी और अंग्रेजी श्रेणियों में अलग-अलग नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
सेल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री अमरेंदु प्रकाश ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, ÷सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता ड्ड 2025 के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई! इस साल का विषय, ÷सेल: खुशियों की संस्कृति का निर्माण, जहाँ हर मुस्कान मायने रखती है,÷ वास्तव में बहुत प्रभावशाली रहा। यह देखकर बेहद प्रेरणा मिलती है कि 80त्न विजेता, यानी 10 में से 8 विजेता महिलाएं हैं। देश भर से मिली विविध कहानियां खूबसूरती से दर्शाती हैं कि कैसे सेल स्टील देश की प्रगति का आधार है और देश के लोगों जीवन को खुशहाल बनाने में लगा हुआ है। सेल की लोगों के जीवन में खुशहाली लाने की जीवंत संस्कृति से भरपूर प्रत्येक कहानी ने भारत के लोगों के साथ सेल के बंधन को मजबूत किया, जिसने देश के सामूहिक सपनों में इस्पात की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है, जो वास्तव में एक नए भारत की भावना को दर्शाता है।÷
सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025÷ फरवरी 2025 में लांच की गई थी, जिसमें सेल के मौजूदा और सेवानिवृत्त सभी सेल कार्मिकों और उनके परिवारों सहित, सभी भारतीय नागरिकों से हिंदी या अंग्रेजी में, 800 शब्दों की रचनात्मक कहानियों को आमंत्रित किया गया था।

अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई: शराबी प्रभारी प्राचार्य निलंबित

रायपुर अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई।

सदन में हंगामा,कांग्रेस ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर किया बहिर्गमन

कांग्रेस के भूपेश बघेल एवं भाजपा के धरमलाल कौशिक ने सरकार को घेरा

सरकार ने जल जीवन मिशन का लक्ष्य पूरा किया -अरूण साव

रायपुर । विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जल जीवन मिशन में निर्धारित लक्ष्य से कम काम तथा अनियमितता को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल द्वारा उठाए गए प्रश्न का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरूण साव द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर सदन का बहिर्गमन कर दिया।

विधानसभा के मानसून सत्र में आज कांग्रेस के भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन में हुए अनियमितता का मामला सदन में उठाया। लोक स्वास्थ्य मंत्री अरूण साव ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में फर्जी काम हुआ था। 35 लाख घरों में कनेक्शन देने का वादा किया था लेकिन सिर्फ 15 लाख घरों में कनेक्शन दिया गया। कांग्रेस शासन काल में फर्जी जल टंकियां बनाई गई जिसके कारण मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य छग के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ एवं पेयजल उपलब्ध कराना है।

भूपेशबघेल ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन में निर्धारित लक्ष्य से कम काम किया गया है। भारसाधक मंत्री अरूण साव ने कहा कि भूपेश बघेल का यह आरोप निराधार है। अरूण साव ने आगे कहा कि हमने जो लक्ष्य रखा है वह पूर्ण किया गया है। फर्जी आकड़े कांग्रेस शासन काल में दिये गये थे। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नोकझोंक हुई।

कांग्रेस के भूपेश बघेल ने पूरक प्रश्न के माध्यम से जलजीवन मिशन में हुए कम खर्च का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अनुमानित खर्च जितना था उतना नहीं हो पाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री इसको लेकर बार बार सरकार का मतंव्य स्वस्थ करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लोकस्वास्थ्य मंत्री द्वारा बार बार विभागीय कार्यों की जानकारी दी गई। कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे कार्यक्रम दस लाख कनेक्शन दिये गये जबकि आपके कार्यकाल में बजट में आबंटित पैसा खर्च किया जा रहा है। अरूण साव ने सभी आरोपों को निराधार बताया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने सदन का बहिर्गमन कर दिया गया। विधानसभा में भाजपा के सदस्य एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में लगे भ्रष्टाचार का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया था वह पूरा नहीं हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरूण साव ने बताया कि इस पर पूरी जांच चल रही है। इसमें हुई अनियमितता की शिकायत मिलने पर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा जांच की गई है। आज सदन में जल जीवन मिशन में कामकाज को लेकर सत्ता पक्ष के पक्ष और विपक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे जिसमें भाजपा और कांग्रेस के सदस्य ने भी भाग लिया।

शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार । बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपये की ठगी के एक बड़े मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी महिला श्वेता अवसरिया (उम्र 37 वर्ष), निवासी न्यू चांगोरभाठा, महादेव नगर, रायपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने शेयर बाजार में निवेश कर रकम को दो वर्षों में दोगुना करने का झांसा देकर आम नागरिकों से भारी मात्रा में धन वसूला। पुलिस ने श्वेता अवसरिया से पूछताछ के दौरान 2 बैंक पासबुक, चेक, डेबिट कार्ड, जमीन व सोने-चांदी के जेवरात की खरीदी-बिक्री से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। इससे एक दिन पहले पुलिस ने आरोपी के पति दिवाकर अवसरिया से 4 मोबाइल फोन, 5 बैंक पासबुक, चेक, एटीएम कार्ड, नकदी ?9,71,000, लेनदेन रजिस्टर, जेवर और अन्य दस्तावेज जब्त किए थे। अब तक की जांच में इस ठगी प्रकरण में कुल 4 आपराधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें शासकीय शिक्षक रामनारायण साहू समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेयर ट्रेडिंग में जल्दी मुनाफा दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने कसडोल, लवन, गिधौरी, शिवरीनारायण, महासमुंद और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है, जो आरोपियों की संपत्तियों की कुर्की, तकनीकी विश्लेषण और

साइबर ट्रेसिंग पर काम कर रही है। प्रकरण में पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के साथ भी इस गिरोह द्वारा शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की गई हो, तो वे तुरंत थाना कसडोल या संबंधित पुलिस इकाई को इसकी जानकारी दें। जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश तेज़ी से की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठन कर रहे प्रयास

रायपुर । वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शहर के आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को रोटरी क्लब जेसीज ग्रीन आर्मी, वसुंधरा स्वयं सेवी संगठन एवं स्कूल एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगाए गये पौधों की देखरेख के लिए शपथ ली। ज्ञातव्य है कि वर्षा ऋतु में मानसून के तहत कहीं कहीं खंड वर्षा भी हो रही है। खंड वर्षा ऐसे स्थानों में हो रही है जहां पर मैदानी क्षेत्र है एवं वृक्षों की कमी है। रिंगरोड के आसपास के क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्र के मैदानों में खेल मैदानों को छोड़कर सघन वृक्षारोपण किया गया। रोटरी क्लब की अंजलि शर्मा एवं ग्रीन आर्मी के अमिताभ दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि वृक्षारोपण के साथ ही सरोवर हमारी धरोहर संरक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। जिसके तहत प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी तालाब में सफाई एवं जलकुंभी को हटाया जाएगा।

विश्व जनसंख्या दिवस पर जिले के विभिन्न स्कूलों एवं क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

जशपुरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के प्लॉन ऑफ एक्शन वर्ष 2025-26 के माह जुलाई 2025 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला एवं तालुका स्तर के अधिकार मित्रों -पैरालीगल वॉलीण्टियर्स द्वारा जनसमुदाय तक विधिक जागरूकता के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के प्रयोजनार्थ जशपुर जिले के विभिन्न स्कूलों एवं क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम व शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के अधिकार मित्रों-पैरालीगल वॉलीण्टियर्स द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले समस्या एवं उनके समाधान के संबंध में जिले के स्कूलों एवं विभिन्न क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पैरालीगल वॉलिण्टियर्स द्वारा नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी के संबंध में कानूनी जानकारी, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य, नशा मुक्ति, बालश्रम निषेध, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, नेशनल लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विधिक सहायता-सलाह हेतु पात्रता, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता, मध्यस्थता के संबंध में जानकारी साझा किया गया।

संपादकीय

अजीत डोभाल ने पाक को दिखाया आईना

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने एक बड़ा खुलासा किया। डोवल ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने इन सारी अटकलों को खारिज किया कि पाकिस्तान के हमले में भारत के एयरबेस और फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा था। अजित डोवल ने कहा कि आजकल के ज़माने में दुश्मन को हथियारों के दम पर हराना तो आसान है, लेकिन असली मुश्किल होती है, दुश्मन के प्रोपेगेंडा वॉर को काउंटर करना। डोवल ने कहा कि पाकिस्तान ने एक झूठ फैलाया कि उसने भारत के एयरबेस तबाह कर दिया, हमारे फाइटर जेट्स को गिरा दिया, तमाम बड़े विदेशी अखबारों ने भी इस खबर को छापा, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला एक भी सबूत आज तक किसी ने दिया क्योंकि ये दावा झूठा था। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान के हमले में भारत का एक कांच तक नहीं टूटा।

अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में सहायक पायलट की गलती पकड़ में ।

अजय दीक्षित

12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 171 अहमदाबाद से लन्दन 242 लोगों को लेकर जारही फ्लाइट के मात्र 40 सेकंड बाद मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में सहायक पायलट क्लाइव कुंदर की फ्यूल स्विच लीवर में छेड़छाड़ कर बंद करने की बात सामने आई है। संसार की पहली घटना है कि विमान टेक ऑफ के बाद अचानक थ रस्ट खो कर गिर पड़ा था। घटना में जहाज में बैठे 242 यात्री करूं मेंबर और जमीन पर रह रहे सहित 272 लोग मारे गए जिसमें मेडिकल कॉलेज के छह चिकित्सक भी शामिल थे। एयर इंडिया, यूएस, ब्रिटेन और ड्रीमलाइनर बोइंग के विशेषज्ञों की संयुक्त जांच दल ने 15 पेज की रिपोर्ट जारी की । ब्लैक बॉक्स में दोनों पायलटों की बातचीत से यह तथ्य सामने आया है कि क्लाइव कुंदर को पायलट ने फ्यूल स्विच का लीवर गलती से खींच दिया तो सुमीत साबरबाल ने कहा कि उसने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया है।यह सब तकनीकी बाते हैं जिस पर लंबी बहस होगी। दूसरी ओर अमेरिका की बोइंग ने बयान जारी कर कहा कि फ्यूल स्विच अपने आप बंद नहीं हो सकते हैं। चूंकि दोनों पायलट जीवित नहीं हैं इस लिए कोई कुछ बता सकने वाली स्थिति में नहीं है। क्लाइव कुंदर और सुमीत साबरबाल दोनों मुंबई में रहते हैं उनके शवों की शिनाख्ती 19 जून को हो पाई ।

दोनों पायलटों के परिवार में कई लोग पायलट हैं। पायलटों जीवन शैली बहुत उच्च क्लास की होती है ये लोग अन्य भारतीय की सामान्य नहीं होते हैं बहुत ही बेहतर खुले ख्यालों की होते हैं।एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देर रात तक एंजॉय करना इनकी आदत में होता है।

यह निजी विचार है।

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

नीति आयोग की मानव पूँजी से संबंधित क्रांति

राव इंद्रजीत सिंह द्वारा

भारत जैसे विशाल और वैविध्यपूर्ण देश में प्रगति का वास्तविक पैमाना केवल जीडीपी के आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि वह देश अपनी जनता का कितने बेहतर ढंग से पोषण करता है। मानव पूँजी–हमारी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और उत्पादकता– केवल एक आर्थिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता भी है। पिछले दस वर्षों में, भारत के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक-नीति आयोग के नेतृत्व में एक शांत लेकिन प्रभावशाली क्रांति ने आकार लिया है, जिसने देश द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी अपने नागरिकों, में निवेश करने के तरीके को नए आकार में ढाला है।

एक ऐसे देश में जहाँ 65 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र वाले लोगों की है, तो वह जनसांख्यिकीय लाभांश बेहद दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। लेकिन इस युवा आबादी का विशाल आकार अपने साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी लेकर आता है। प्रमुख चुनौती इस युवा ऊर्जा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास की शक्ति में रूपांतरित करना है। यहीं पर नीति आयोग एक दूरदर्शी उत्प्रेरक के रूप में उभरा है - जो न केवल आज की प्रगति, बल्कि भविष्य की समृद्धि का भी रोडमैप तैयार कर रहा है।

पिछले एक दशक में, नीति आयोग एक थिंक टैंक से एक सुधारवादी साधन और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में विकसित हुआ है, जो आँकड़ों, सहयोग और मानव-केंद्रित डिज़ाइन द्वारा समर्थित साहसिक विचारों के लिए जाना जाता है। इसने नीति-निर्माण को एक शीर्ष-स्तरीय प्रक्रिया से राज्यों, निजी क्षेत्र, वैश्विक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के साथ सह-निर्माण की गतिशील प्रक्रिया में बदल दिया है। इसकी ताकत केवल योजना बनाने में ही नहीं, बल्कि संज्ञान लेने और उन अवधारणाओं को अमली जामा पहनाने में भी निहित है।

इसके मार्गदर्शन में मानव पूँजी की आधारशिला-शिक्षा की पूर्णतया नए सिरे से परिकल्पना की गई है। नीति आयोग ने इस बात को स्वीकार करते हुए कि केवल पहुँच ही पर्याप्त नहीं होती, गुणवत्ता और न्यायसंगतता पर ज़ोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जहाँ नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ने –रटंत शिक्षा से आलोचनात्मक चिंतन, लचीलेपन और व्यावसायिक एकीकरण का रुख करते हुए एक नए युग का सूत्रपात किया। इसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और विषयों के बीच निर्बाध परिवर्तन पर ज़ोर दिया। इसने देश भर में मौजूद 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स में नवाचार को समाहित करते हुए अटल नवाचार मिशन जैसी पहलों के माध्यम से जवाबदेही और कल्पनाशीलता दोनों को सुनिश्चित किया।

भारत के युवाओं को 21वीं सदी के लिए कुशल बनाना इसके मिशन का एक और आधार रहा है। कौशल भारत मिशन को समर्थन देने से लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से वंचित जिलों के महत्वपूर्ण भाग तक व्यावसायिक कार्यक्रमों की पहुँच सुनिश्चित करने तक, नीति आयोग ने कक्षा और करियर के बीच की खाई को पाटने में मदद की है। कौशल भारत मिशन के तहत, 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को तकनीक, उद्योग संबंधों और माँग-आधारित पाठ्यक्रमों के सम्मिश्रण वाली पहलों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। इसने महज प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ही प्रशिक्षण नहीं दिया–अपितु इसने क्षेत्रीय ज़रूरतों का आकलन किया और भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के युवाओं के लिए वास्तविक आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलने वाले कार्यक्रम तैयार किए।

इसके साथ ही साथ, इसने गतिशील, समावेशी श्रम बाज़ार का समर्थन किया। इसने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को–मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित चार सरलीकृत संहिताओं में युक्तिसंगत बनाने में सहायता प्रदान की। इन सुधारों ने नियोक्ता के लचीलेपन को श्रमिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया, जिससे विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ, जो भारत के कार्यबल का बहुसंख्यक हिस्सा हैं। अनुपालन को सरल बनाकर और औपचारिकता को प्रोत्साहित करके कार्यस्थल केवल अधिक उत्पादक ही नहीं, बल्कि अधिक मानवीय भी बना।

अक्सर लागत के रूप में देखी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा को निवेश के रूप में नए सिरे से परिभाषित किया गया। नीति आयोग ने प्रतिक्रियात्मक उपचार से अग्रसक्रिय स्वास्थ्य का रुख किए जाने को मूर्त रूप प्रदान करने में मदद की। नीति आयोग द्वारा समर्थित और निरीक्षित प्रमुख आयुष्मान भारत योजना ने 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जबकि 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने प्राथमिक देखभाल को जमीनी स्तर तक पहुँचाया। कार्यक्रमों ने पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों को लक्षित किया–जिनका उद्देश्य केवल बीमारों का उपचार करना ही नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ रखना भी था। कोविड-19 महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती की अभूतपूर्व परीक्षा ली। नीति आयोग ने संकट की इस घड़ी का बड़ी दृढ़ता और विश्वास से सामना करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के साथ मिलकर संक्रमण के पैटर्न का मॉडल तैयार किया, न्यायसंगत चिकित्सा संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित किया और टेलीमेडिसिन के लिए ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए। महामारी के बाद के इसके विजन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्गों और आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे पर ज़ोर देते हुए केवल रिकवरी पर ही पहीं, बल्कि तत्परता पर भी ज़ोर दिया।

इन क्षेत्रों से परे, नीति आयोग उद्यमिता और नवाचार के लिए प्रकाश स्तंभ रहा है। स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों ने विचारों के फलने-फूलने के लिए उपजाऊ इकोसिस्टम तैयार किया है। महत्वपूर्ण चरणों में नीतिगत समर्थन, इनक्यूबेशन और मार्गदर्शन मिलने की वजह से फिनटेक, एडटेक, एग्रोटेक, हेल्थटेक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हजारों स्टार्ट-अप आज फल-फूल रहे हैं। ये व्यवसाय मात्र ही नहीं हैं; बल्कि ये रोजगार सृजनकर्ता और समस्या का समाधान करने वाले भी हैं, जो एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रहे हैं।

लेकिन संभवतः इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इसके द्वारा साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण की संस्कृति को संस्थागत रूप दिया जाना रही है। इसने विशाल आँकड़ों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और कठोर निगरानी ढाँचों का लाभ उठाकर नीतियों का अनुकूल, जवाबदेह और ज़मीनी हक़ीक़तों के अनुरूप बना रहना सुनिश्चित किया है। चाहे भारत का पहला एसडीजी सूचकांक जारी करना हो, कार्य निष्पादन के मानकों पर राज्यों को मार्गदर्शन देना हो, या नीति निर्माण के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करना हो, नीति आयोग ने वैज्ञानिक चिंतन को शासन के केंद्र में ला दिया है।

विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों में संयोजन और समन्वय स्थापित करने की इसकी क्षमता ने इसे एक परामर्शदायी निकाय से कहीं अधिक बना दिया है–यह विकास के अंतःकरण का रक्षक बन गया है। इसने कार्य निष्पादन - आधारित रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया, हाशिये पर पड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम किया और सर्वोत्तम प्रथाओं को देश में लाने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ सहभागिता की। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का बढ़ता कद और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूनेस्को जैसी संस्थाओं से मिली प्रशंसा इस प्रयास के प्रति दुनिया के सम्मान को दर्शाती है।

नीति आयोग ने केवल लक्ष्य हासिल करने से कहीं बढ़कर, टिकाऊ, समावेशी और भविष्य के अनुरूप प्रणालियाँ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता –स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से लेकर हरित गतिशीलता तक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर कार्यस्थलों में महिला-पुरुष समानता तक- हर पहल में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदय अब कोई दूर का सपना नहीं रह गया है–यह जनता को राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति मानने वाली नीतियों के जरिए संचालित एक प्रगतिशील कार्य बन चुका है। नीति आयोग ने विकास के इर्द-गिर्द के विमर्श को ऊपर उठाते हुए हमें याद दिलाया है कि सच्ची प्रगति गगनचुम्बी इमारतों या सबसे बड़े कारखानों से नहीं, बल्कि जनता की ताकत, स्वास्थ्य और गरिमा से मापी जाती है। ऐसा करके, यह महज एक थिंक टैंक से कहीं बढ़कर बन गया है। यह युवा, महत्वाकांक्षी भारत–एक ऐसे भारत की धड़कन बन गया है जो सपने देखता है, हिम्मत करता है और कर्म करता है। और इस कहानी के केंद्र में वह शांत विश्वास है कि जब आप लोगों में निवेश करते हैं, तो आप केवल एक बेहतर अर्थव्यवस्था का ही नहीं, बल्कि एक बेहतर राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं।

[लेखक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना और संस्कृति राज्य मंत्री हैं]

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भारत की कूटनीतिक जीत

गिरीश पांडे

एससीओ और क्वाड के बाद एक बार फिर 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डि जिनेरियो में आयोजित दो दिवसीय 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकवादी घटना की गूंज सुनाई दी।

उल्लेखनीय है कि लगभग 15 दिनों के भीतर ये तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए और भारत ने ऑपरेशन सिन्दूर के बाद पहली बार इन सम्मेलनों में भाग लिया था।

इस बार ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की मेजबानी में हुआ, जिसमें पुराने 5 देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के अलावा नये सदस्य देशों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ने हिस्सा लिया। ब्राजील ने 1 जनवरी, 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। इस बार की थीम रही-'समावेशी और टिकाऊ वैंकि शासन के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग मजबूत करना' हालांकि, चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान में पहलगाम की घटना का उल्लेख न होने की वजह से उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसलिए वह बयान जारी नहीं हो सका, लेकिन क्वाड के विदेश मंत्रियों की अमेरिका में आयोजित बैठक के बाद क्वाड के साझा बयान में पहलगाम साजिशकर्ताओं, हमलावरों और फंडिंग करने वालों को सजा दिलाने की मांग की गई और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान किया गया है कि वे जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मिलकर काम करें। निश्चित तौर पर एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए एक झटका क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर ये दोनों देश बेनकाब हुए हैं।

ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ब्रिक्स घोषणा-पत्र में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यही नहीं, ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों की सीमापार आवाजाही, इसके वित्त-पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने के लिए भी अपनी वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के शिकार लोगों और इसे शह देने वालों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मोदी का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि पहलगाम घटना भारत की आत्मा, पहचान और सम्मान पर घातक हमला था, आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल भारत पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि पूरे मानवता पर किया गया प्रहार था।

आतंकवाद की बर्बरता पर जीरो टॉलरेंस की मांग करते हुए उन्होंने सूचित किया कि आतंकवादी संगठनों पर कड़ी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संवाद और राजनीतिक मार्ग द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय मसलों के समाधान पर अमल करेगा, जिससे वैंकि शांति बनी रहे। इसके अलावा, मोदी ने ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ 'बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर आयोजित संपर्क सत्र में भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बहुध्रुवीय और समावेशी वि व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, अभी तक चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का प्रयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को बचाने के लिए ही किया है। अब जिस प्रकार से एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स में आतंकवाद को समूल नाश करने की प्रतिबद्धता सदस्य देशों ने व्यक्त की है, देखने की बात होगी कि क्या चीन का भी इस मसले पर हृदय परिवर्तन होगा? दूसरी ओर ब्रिक्स से अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक प्रकार से खौफ खाए हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने जब अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हुए हालिया हमले और डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ व्यापार शुल्क (टैरिफ) से वैंकि व्यापार पर बुरा असर पड़ने की बात कही और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने नाटो की तरफ से सैन्य खर्च बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि शांति की तुलना में युद्ध में निवेश करना हमेशा आसान होता है तो इसे लेकर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। उन्होंने ब्रिक्स देशों को नई चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका की विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेमलन का तेजी से बदलते वैंकि घटनाक्रम में अत्यंत महत्त्व है और यह समूह बहुध्रुवीय वि के निर्माण के साथ-साथ ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनता जा रहा है और जिसका भारत बराबर पैरोकार रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत की ब्रिक्स में बढ़ती भूमिका स्वयंसिद्ध है। देखना है, अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स आगे क्या रूप लेता है?

एससीओ और क्वाड के बाद एक बार फिर 67 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डि जिनेरियो में आयोजित दो दिवसीय 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकवादी घटना की गूंज सुनाई दी। उल्लेखनीय है कि लगभग 15 दिनों के भीतर ये तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए और भारत ने ऑपरेशन सिन्दूर के बाद पहली बार इन सम्मेलनों में भाग लिया था।

इस बार ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की मेजबानी में हुआ, जिसमें पुराने 5 देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के अलावा नये सदस्य देशों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ने हिस्सा लिया। ब्राजील ने 1 जनवरी, 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। इस बार की थीम रही-'समावेशी और टिकाऊ वैंकि शासन के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग मजबूत करना' हालांकि, चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान में पहलगाम की घटना का उल्लेख न होने की वजह से उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसलिए वह बयान जारी नहीं हो सका, लेकिन क्वाड के विदेश मंत्रियों की अमेरिका में आयोजित बैठक के बाद क्वाड के साझा बयान में पहलगाम साजिशकर्ताओं, हमलावरों और फंडिंग करने वालों को सजा दिलाने की मांग की गई और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान किया गया है कि वे जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए अंतराष्ट्रीय कानून के तहत मिलकर काम करें।

निश्चित तौर पर एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए एक झटका क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर ये दोनों देश बेनकाब हुए हैं। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ब्रिक्स घोषणा-पत्र में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यही नहीं, ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों की सीमापार आवाजाही, इसके वित्त-पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने के लिए भी अपनी वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के शिकार लोगों और इसे शह देने वालों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

मोदी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि पहलगाम घटना भारत की आत्मा, पहचान और सम्मान पर घातक हमला था, आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल भारत पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि पूरे मानवता पर किया गया प्रहार था। आतंकवाद की बर्बरता पर जीरो टॉलरेंस की मांग करते हुए उन्होंने सूचित किया कि आतंकवादी संगठनों पर कड़ी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संवाद और राजनीतिक मार्ग द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय मसलों के समाधान पर अमल करेगा, जिससे वैंकि शांति बनी रहे। इसके अलावा, मोदी ने ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ 'बहुपक्षवाद, आर्थिक-वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर आयोजित संपर्क सत्र में भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बहुध्रुवीय और समावेशी वि व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, अभी तक चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का प्रयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को बचाने के लिए ही किया है। अब जिस प्रकार से एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स में आतंकवाद को समूल नाश करने की प्रतिबद्धता सदस्य देशों ने व्यक्त की है, देखने की बात होगी कि क्या चीन का भी इस मसले पर हृदय परिवर्तन होगा? दूसरी ओर ब्रिक्स से अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक प्रकार से खौफ खाए हैं।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने जब अमेरिका का नाम लिए बिना ईरान पर हुए हालिया हमले और डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ व्यापार शुल्क (टैरिफ) से वैंकि व्यापार पर बुरा असर पड़ने की बात कही और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने नाटो की तरफ से सैन्य खर्च बढ़ाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि शांति की तुलना में युद्ध में निवेश करना हमेशा आसान होता है तो इसे लेकर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। उन्होंने ब्रिक्स देशों को नई चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका की विरोधी नीति का समर्थन करते हैं तो उन पर 10 फीसद अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेमलन का तेजी से बदलते वैंकि घटनाक्रम में अत्यंत महत्त्व है और यह समूह बहुध्रुवीय वि के निर्माण के साथ-साथ ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनता जा रहा है और जिसका भारत बराबर पैरोकार रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत की ब्रिक्स में बढ़ती भूमिका स्वयंसिद्ध है। देखना है, अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स आगे क्या रूप लेता है?

यह निजी विचार है।

युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण गंभीर चुनौती

प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्र. गुप्ता

युवाओं में नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में सीना तानकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी 'विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024' के अनुसार 29.2 करोड़ से भी अधिक लोग पूरे विश्व में मादक पदार्थ के सेवन में लिप्त हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या में पिछले दशक की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नशे के प्रति इतनी रु झान मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर संकट की ओर संकेत कर रही है।

भारत में भी युवा बड़ी संख्या में नशाखोरी की चपेट में हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती रु चि को एक पीढ़ीगत संकट बताया है। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के तीसरे एपिसोड में 14 दिसम्बर 2014 को पूरी संवेदना के साथ देश के युवाओं से नशाखोरी से बाहर आने की विशेष अपील की थी। साथ ही उन्होंने युवाओं को विास दिलाया कि राष्ट्र के सामने मौजूद इस गंभीर संकट से निपटने के लिए वे युवा वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश के लगभग 20 प्रतिशत लोग नशे की चपेट में हैं।

इनमें 1.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। 10 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग वाले लगभग 1.5 करोड़ किशोर भी इस खतरे की चपेट में हैं, जिनमें चिंताजनक संख्या में छोटी-छोटी बेटियां भी हैं। 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज 2017' के अनुसार पूरी दुनिया में 7.30 लाख लोग अवैध ड्रग्सं के सेवन के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें से 22 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु भारत में भी हुई। एन.सी.आर.बी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ही पूरे देश भर में ड्रग्स से परेशान होकर लगभग 7800 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले अधिक लोग रहे। कष्टदायक स्थिति ये है कि हमारे कुछ युवा नशे के दुष्प्रभाव के कारण मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं।

देश के लगभग 45 मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अस्पतालों में पिछले 10 वर्षों में भर्ती लोगों में 20 प्रतिशत नशे के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ माने गए। नशे के कारण मानसिक बीमारी के शिकार लोगों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में नशे से संबंधित एफ.आई.आर की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 3 करोड़ से अधिक लोग भांग के नशे में लिप्त हैं, जिनमें से 72 लाख से अधिक लोग इसकी वजह से अस्वस्थ हैं। 10 लाख के आसपास लोग इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स लेते हैं, जबकि 10 करोड़ से अधिक लोग अनेक अवैध नशीले पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही इस संकट से जूझ रहा है।

अमेरिका, फ्रांस इत्यादि देशों के साथ सीरिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, रूस, ब्राजील इत्यादि देश भी इस समस्या से ग्रसित हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण दुनिया में सबसे अधिक मौतें अमेरिका और फ्रांस में ही हुई हैं। सीरिया में तो सरकार ने ही नशीली दवाओं के व्यापार को वित्त पोषित किया है। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2017 के अनुसार केवल अमेरिका में ही नशीली दवाओं के कारण 70 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भारत की शिक्षण संस्थाओं के आसपास चाय-नाश्ते की दुकानों, जनरल स्टोर्स इत्यादि के माध्यम से युवाओं को ड्रग्स और अन्य नशीले पदाथरे के दलदल में घसीटा जा रहा है। भारत सरकार की ओर से समय-समय पर अनेक आवश्यक कदम उठाए जाते रहे हैं। एक तरफ सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से ड्रग्स के अवैध व्यापार पर लगातार छापेमारी करके उन नशीले पदाथरे को नष्ट कर रही है तो दूसरी ओर इसमें लाभ कमाने की दृष्टि से जो असामाजिक तत्व लगे हुए हैं, उनको कानून के कड़े प्रावधानों के द्वारा दंडित भी कर रही है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नशाखोरी को समाप्त करने के लिए 'ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत प्रयास किए जा रहे हैं। **यह निजी विचार है।**

ISS से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल का संकल्प

आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है।

15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अन्तरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है।

आज मंत्रिमंडल, देश के साथ मिलकर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया।

ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए। इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है। ये अन्तरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है, एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है।

मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ढ्ढस्क्रह्र के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है। उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया।

ढ्ढस्स् पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने ×ढ्ढश्ढ्ढ-4 क्रू और श्च×श्चद्गस्त्रढ्ढह्लढ्ढशठ्ठ 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए। ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है।

उन्होंने माइक्रोग्रैविटी से जुड़े कई प्रयोग किए। Muscle regeneration, शैवाल एवं सूक्ष्मजीवों की ग्रोथ और अंतरिक्ष में फसलों की क्षमता से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें शामिल थे। इस मिशन में माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और इंसान की सोचने-समझने की क्षमता पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ। सायनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे कई अहम विषयों पर काम किया गया।

इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन को लेकर समझ और गहरी होगी, माइक्रोग्रैविटी साइंस में हम आगे बढ़ेंगे। भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है। शुभांशु शुक्ला के मिशन की इस सफलता ने भारत को अपने इन लक्ष्यों के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है। भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है। उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमताओं पर उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है।

सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह, आदित्य-रु मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है। ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण हैं।

सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं, उससे भारत की स्पेस इकॉनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और technology-driven development का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे।

प्रयागराज में मानसून के मौसम में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण आंशिक रूप से जलमग्न दशाश्वमेध घाट पर लोग।

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने देहरादून में भारी बारिश के बाद उफनते नाले में फंसे तीन लोगों को बचाया।

आयकर विभाग ने कटौतियों और छूटों के फर्जी दावों पर की कार्रवाई : केंद्र

नई दिल्ली एजेंसी केंद्र सरकार ने कहा कि आयकर विभाग ने देश भर में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कटौती और छूट के फर्जी दावों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर नजर रखना है। 150 कैंपस में चल रहे वेरिफिकेशन अभियान से डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है, जो इन योजनाओं के पीछे के नेटवर्क को खत्म करने और कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।

जांच में कुछ आईटीआर तैयार करने वालों और बिचौलियों द्वारा संचालित संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो फर्जी कटौती और छूट का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इन धोखाधड़ी वाली फाइलिंग में लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग शामिल है, कुछ लोग अत्यधिक रिफंड का दावा करने के लिए झूठे टीडीएस रिटर्न भी जमा करते हैं। यह कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लाभों के दुरुपयोग के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई है, जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों की मिलीभगत से किया जाता है। संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए, आयकर विभाग ने थर्ज पार्टी स्रोतों, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और एडवांस एआई उपकरणों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों का लाभ उठाया है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में हाल ही में की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाइयों से इन निष्कर्षों की पुष्टि होती है, जहां विभिन्न समूहों और संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के दावों के सबूत पाए गए। आधिकारिक बयान के अनुसार, विश्लेषण से धारा 10(13ए), 80जीजीसी, 80ई, 80डी, 80ईई, 80ईईबी, 80जी, 80जीजीए और 80डीडीबी के तहत कटौतियों के दुरुपयोग का पता चलता है। बिना किसी वैध औचित्य के छूट का दावा किया गया है।

गिरिराज सिंह ने प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की

16वां इंडिया ट्रेंड फेयर 2025 भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने का सबसे बड़ा मंच है

पीआईबी

केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जापान की आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं और 15 जुलाई 2025 को टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेंड फेयर 2025 का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से सीधे जुड़ने के सबसे बड़े प्लेटफार्मों में से एक है और इससे दोनों देशों का कपड़ा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। श्री गिरिराज सिंह ने ज़िपर और फास्टनिंग उत्पादों की विश्व की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी वाईकेके कॉर्पोरेशन के प्रमुख से मुलाकात की। हरियाणा में पहले से ही कार्यरत वाईकेके ने अन्य राज्यों में भी विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की। श्री सिंह ने उन्हें पीएम मित्र पार्कों में निवेश के लिए आमंत्रित किया, जिसका उन्होंने स्वागत किया गया।

वर्कवियर और फंक्शनल अपैरल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वर्कमैन कंपनी के अध्यक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री महोदय ने भारत के बढ़ते विनिर्माण इकोसिस्टम पर प्रकाश डाला। वर्कमैन कंपनी ने पीएम मित्रा ढांचे के तहत भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई।

श्री सिंह ने डिजिटल और औद्योगिक मुद्रण क्षेत्र की वैश्विक कंपनी कोनिका मिनोल्टा के साथ भी चर्चा की। उन्होंने कंपनी को भारत में परिचालन का विस्तार करने और ईएसजी एवं स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। कंपनी ने भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने के अवसर का स्वागत किया।

इसके अलावा, श्री गिरिराज सिंह ने फाइबर, औद्योगिक सामग्री और विशिष्ट वस्त्र उद्योग में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के समूह, असाही कासेई कॉर्पोरेशन के नेतृत्व से भी मुलाकात की। कंपनी ने 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' पहल के तहत निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई।

केंद्रीय मंत्री ने जापान के टोक्यो में 20 अरब डॉलर के समूह असाही कासेई की नेतृत्व टीम से मुलाकात की

दिन का समापन टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में एक रोड शो और उद्योग जगत के साथ बातचीत के साथ हुआ, जिसमें कपड़ा क्षेत्र पर केंद्रित भारत-जापान साझेदारी का उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की 100 से ज़्यादा हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें भारत के राजदूत श्री सिबी जॉर्ज और कपड़ा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री गिरिराज सिंह ने वैश्विक कपड़ा केंद्र के रूप में भारत की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी और जापानी कंपनियों को भारत के कपड़ा क्षेत्र के विकास में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग नवा रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक 834/NIT-5/2025–26/व.ले.लि. नवा रायपुर दिनांक 14/07/2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :–

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ No of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
5 T0022	रियाबंद जिले के गरियाबंद में नव प्रस्तावित सखी वन स्टॉप सेंटर, सीडब्ल्यूसी और जेजेबी भवन में विद्युतीकरण कार्य (जमा मद)	5.67
5 T0023	एसडीएम कार्यालय राजिम जिला गरियाबंद में विद्युतीकरण और प्रोजेक्टरए एलईडीए एसी की आपूर्तिए स्थापनाए परीक्षण और कमीशनिंग विद्युतीकरण कार्य (जमा मद)	4.60
5 T0024	छुरा जिला गरियाबंद में नव प्रस्तावित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय भवन में विद्युतीकरण कार्य (जमा मद)	4.62

नोट :–निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 28/07/2025 अपरान्ह 5:30 बजे तक है ।

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है । इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है ।

शर्तें :– 1) उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

G-25260211/2

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग नवा रायपुर छ.ग.

टाटा टेक्नोलॉजीज का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ क्रमिक आधार पर 9.8 प्रतिशत गिरा

मुंबई एजेंसी। टाटा टेक्नोलॉजीज ने सोमवार को जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ तिमाही आधार पर 9.8 प्रतिशत घटकर 170.28 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 188.87 करोड़ रुपए था।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी के परिचालन राजस्व में भी गिरावट आई है, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में तिमाही आधार पर 3.2 प्रतिशत और सालाना आधार पर 1.9 प्रतिशत घटकर 1,244 करोड़ रुपए रह गया।

यह गिरावट मुख्य रूप से इसके दोनों प्रमुख क्षेत्रों सेवाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों में कमजोर प्रदर्शन के कारण हुई।

सेवा क्षेत्र से राजस्व तिमाही आधार पर 5.9 प्रतिशत और सालाना आधार पर 2.2 प्रतिशत घटकर 963 करोड़ रुपए रह गया, जबकि प्रौद्योगिकी समाधान क्षेत्र में भी तिमाही आधार पर 3.2 प्रतिशत और सालाना आधार पर 1.9 प्रतिशत घटकर 280 करोड़ रुपए रह गया।

परिचालन के मोर्चे पर, ईबीआईटीडीए 201 करोड़ रुपए रही, जो पिछली तिमाही की तुलना में 14.3 प्रतिशत और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।

टेस्ला मॉडल वाई भारत में 60 लाख रुपए में लॉन्च

मुंबई ,एजेंसी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने मंगलवार को भारत में अपनी रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) मॉडल वाई कार लॉन्च की, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव की कीमत इसकी वेबसाइट पर पब्लिश्ड प्राइस लिस्ट के अनुसार 67.89 लाख रुपए होगी। मॉडल वाई की अमेरिका में शुरुआती कीमत 44,990 डॉलर, चीन में 263,500 युआन और जर्मनी में 45,970 यूरो है। भारत में इसकी कीमत किसी भी फेडरल टैक्स प्रोत्साहन से पहले, अमेरिका में इसकी मूल कीमत से लगभग 15,000 डॉलर का अंतर दर्शाती है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर छत्तीसगढ़

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 41/नि.शा./का.अ./लो.स्वा.यां./खण्ड, रायपुर, दिनांक 04.07.2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:–

स. क्र.	कार्य का नाम	राशि (रू.लाख में)
1	उपखण्डीय जल परीक्षण प्रयोगशाला अभनपुर लो.स्वा.यां. विभाग में ग्लासवेयर सामग्री प्रदाय करने का कार्य।	4.19
2	उपखण्डीय जल परीक्षण प्रयोगशाला अभनपुर लो.स्वा.यां. विभाग में केमिकल सामग्री प्रदाय करने का कार्य।	4.275

उपरोक्त कार्यो की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18.07.2025 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

G-252602164/1

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
रायपुर छत्तीसगढ़

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

विधायक कश्यप ने विधानसभा में उद्योगों के लिए अधिग्रहित जमीन का मामला उठाया

जांजगीर चांपा / विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विधायक ब्यास कश्यप ने जिला जांजगीर-चांपा में उद्योग स्थापना के लिए अधिग्रहित जमीन, श्रमिक कल्याण हेतु संचालित योजनाओं तथा जिला जांजगीर-चांपा क्षेत्र के नगरीय निकायों में जल आवर्धन योजना एवं अन्य योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति के संबंध में प्रश्न पूछे। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2022 से जून 2025 तक पॉवर प्लांट या अन्य उद्योग स्थापना के लिए हुए एम.ओ.यू., भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण के संबंध सवाल पूछे। जवाब में उद्योग मंत्री के द्वारा बताया गया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2022 से जून 2025 तक कोई एम.ओ.यू. नही हुआ है तथापि इसके स्थान पर नवीन प्रणाली के अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में जांजगीर-चांपा में एक इकाई मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड बेंगलुरू, कर्नाटक के लिए ''इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट'' पत्र जारी किया गया है। जवाब में बताया गया कि मेसर्स जांजगीर थर्मल पॉवर लिमिटेड द्वारा उद्योग स्थापना में रूचि नही लिए जाने एवं भू-आबंटन हेतु जमा कराई गई तदर्थ अग्रिम प्रब्याजि राशि वापस मांग किये जाने के फ्लस्वरूप जमा कराई गई राशि इकाईयों को सीएसआईडीसी द्वारा स्वयं के मद से वापस की जा चुकी है। विभाग द्वारा आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त में से ग्राम गतवा की कुल 100 एकड़ भूमि मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स

लिमिटेड (मेसर्स बी.ए.एम.एल.) को आबंटन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी तरह विधानसभा जांजगीर-चांपा के मेसर्स कर्नाटक पावर लिमिटेड को ग्राम गोधना, कुकदा, सलखन में भूमि आबंटित की जा चुकी है। इकाई द्वारा उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु मांग की गई मुआवजा एवं सेवा शुल्क राशि का भुगतान सीधे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी को किया गया है। सीएसआईडीसी द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नही किया गया है।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर के जनपद पंचायत नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत धुरकोट के ऑगनबाडी केन्द्र 06 में ऑगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर ने बताया कि ग्राम पंचायत धुरकोट के ऑगनबाडी केन्द्र 06 में सहायिका पद रिक्त होने के फ्लस्वरूप उक्त ग्राम के 8 वीं उत्तीर्ण तथा 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक महिला अभ्यर्थी 30 जुलाई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर (जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर के पीछे पुराना बाल संरक्षण गृह) में आवेदन पत्र कार्यालयीन दिवस में सीधे जमा कर सकते है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

तीन आरोपीयों से 45 लीटर महुआ शराब जब्त

आबकारी विभाग की कार्यवाही

जांजगीर चांपा / तीन आरोपीयों से 45 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ तीन आरोपी पकड़े गए हैं । यह कार्यवाही आबकारी आयुक्त श्याम धावड़े एवं कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार व प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमति नीलिमा दीप्रस्कर के विशेष मार्गदर्शन में जिला-जांजगीर में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण ,परिवहन एवं भंडारण पर कार्यवाही की गई ।

इस कार्यवाही में दिनांक 15 जुलाई 2025 को 45 बल्क लीटर हाथभट्ठी महुआ शराबजब्त कर धारा-34(2) के तहत 3 प्रकरण बनाने के साथ 1 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं । इस कड़ी में वृत्त जांजगीर के आरोपी प्रशांत कुमार सोनवानी पिता सीताराम उम्र-21 वर्ष साकिन-हरदी थाना-बलौदा

ज़िला जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)के आधिपत्य से 7 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब , वृत्त-चांपा के आरोपी परमेश्वर धनवार पिता सुखसिंह उम्र-21 वर्ष साकिन-सोनईडीह थाना-बम्हनीडीह ज़िला -जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)के आधिपत्य से 8 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब व वृत्त-अकलतरा के आरोपी राकेश कुमार गोंड पिता लच्छी राम उम्र-22 वर्ष साकिन-बड़े अमेरी कोटमी सोनार थाना-अकलतरा ज़िला -जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)के आधिपत्य से मोटरसाइकिल पल्सर गाड़ी न.CG11BJ 1847 वाहन से 30 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब बरामद होने पर उक्त आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) की कार्यवाही किया गया । उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विकास सांडे,यीवरेश कुमार ,शिल्पा दुबे एवं मुख्य आरक्षक छेदीलाल लहरे ,देवदत जायसवाल ,अनवर मेनन, गणेश चेलकर आरक्षक गीता कमल ,शीतला कौशिक एवम नगर सैनिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चाम्पा ने किया विद्युत विभाग चाम्पा का घेराव

चांपा / संवाददाता

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार व जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राज्य की भाजपा सरकार द्वारा लगातर चौथी बार बिजली बिल की वृद्धि के विरोध में ब्लाक कांग्रेस कमेटी चाम्पा, द्वारा बिजली ऑफिस चाम्पा का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया । सुबह 10.30 बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एकत्रित होना शुरू हो गया साथ ही साथ आम नागरिक भी त्रस्त होते कार्यक्रम में शामिल हुए ।

भारी संख्या में महिलाएँ भी अपना विरोध दर्ज कराने पहुँची , सर्वप्रथम बिजली ऑफिस मोड़ पर कांग्रेसजन एकत्रित होते हुए व माइक से सभी को संबोधित करते हुए ब्लाक अध्यक्ष सुनील साधवानी ने बताया की प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चौथी बार बिजली में वृध्दि की गई और स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल से लोग परेशान है । कार्यकारी जिलाध्यक्ष रमेश पैगवार ने भी भाजपा सरकार पर भड़ास निकाली । पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित पूर्व राजेश अध्यक्ष अग्रवाल, जय थवाईत, नेता प्रतिपक्ष हरीश पांडेय , जिला प्रवक्ता नागेंद्र गुप्ता , चेम्बर अध्यक्ष सुनील सोनी , प्रकाश अग्रवाल ,जिला महामंत्री गुलशन सोनी , युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पंकज शुक्ला , वरिष्ठ कांग्रेसी समद बेग जी ने भी बिजली बिल वृद्धि पर जमकर भड़ास निकाली व विरोध दर्ज किया ,ततपश्चात सभी कांग्रेस माइक में विष्णुदेव साय हाय हाय भाजपा शर्म करो , छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद बिजली दर कम करो के नारों के साथ विद्युत विभाग के मेन गेट पर पहुँचे । सभी ने मिलकर बिजली बिल को जलाकर अपना विरोध किया भारी । संख्या में पुलिस बल रहा कार्यकर्त्ताओ से हल्की झूमाझटकी के साथ सी.एस.ई.बी चाम्पा ई ई भारद्वाज जी व जे. ई. महेश जायसवाल को उपस्थित कांग्रेस जनों ने ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम समापन की घोषणा की । कार्यक्रम का संचालन ब्लाक कांग्रेस कमेटी के कार्य.अध्यक्ष सुनील सोनी ने किया व आभार पूर्व ब्लाक अध्यक्ष किशन सोनी ने किया । कार्यक्रम में मुख्यरूप से रमेश पैगवार , सुनील साधवानी दिनेश शर्मा राजेश अग्रवाल जय थवाईत नागेंद्र गुप्ता सुनील सोनी किशन सोनी अमरजीत सलूजा प्रकाश अग्रवाल गुलशन सोनी पंकज शुक्ला पार्षद हरीश पांडेय अनिल रात्रे पवन साहू जिब्बू आर्य पुरषोत्तम देवांगन दुर्गा कुर्रे गिरधर देवांगन परदेशी केंवट वरिष्ठ कांग्रेसी श्रीमती शांति सोनी जिला महामंत्री सेवकलाल देवांगन पूर्व पार्षद गोविंद देवांगन रंजन कैवर्त रामबाई स्वर्णकार समद बेग हासिम खान अनिता प्रकाश स्वाति बंशीयर राजकुमार सिदार राजू शर्मा आसन दीवान बबलू महन्त सिद्धगोपाल शुक्ला रमेश बरेठ अरुण देवांगन युवा शक्ति में विशाल केड़िया विक्की मनवानी जीवन बंजारे संजय देवांगन हसन कुरैशी राजू देवांगन राकेश जोशी ऑटो संघ के अध्यक्ष राकेश कर्ष काशी पटवा संजय साधवानी नोहर देवांगन पंकज साधवानी सुमित चौहान राकेश साधवानी विष्णु गाड़ा राम साधवानी इतवारी यादव मुकेश साधवानी रामलाल यादव अविनाश महन्त राजकुमार यादव छोटू यादव ध्रुव चौहान शंभु दयाल निखलेस बोस सहित भारी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे ।

कलेक्टर ने जिले में पदस्थ तहसीलदारों के पदस्थापना में किया आंशिक संशोधन

जांजगीर-चांपा / छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत कर जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ किये जाने के फ्लस्वरूप कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जिले में पदस्थ तहसीलदारों के मध्य पूर्व में किये गये पदस्थापना आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार बम्हनीडीह श्री उमाकांत जायसवाल को तहसीलदार नवागढ़, तहसीलदार शिवरीनारायण श्री अविनाश चौहान को तहसीलदार बम्हनीडीह, श्री टेकेन्द्र नुरूटी को तहसीलदार शिवरीनारायण, अति0 तहसीलदार नवागढ़ श्रीमती करूणा आहेर को अति0 तहसीलदार पामगढ़ में एवं श्री चंद्रकांत चंद्रवंशी को प्रभारी तहसीलदार के पद पर उप तहसील राहौद में पदस्थ किया गया है।

9 साल पहले खरीदी गई कैंसर की मशीन आखिर कब होगी चालू : शेषराज हरबंश

सदन में गूंजा मेकाहारा में बंद पड़े मशीनों की मरम्मत का मामला

जांजगीर चांपा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तीसरे दिन सदन में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) की बंद पड़ी कैंसर की जांच मशीनों और मशीनों की खरीदी प्रक्रिया का मुद्दा विधानसभा गूंजा। इस मामले में पामगढ़ के कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा।

कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन की कार्यवाही के दौरान मेकाहारा में बंद पड़ी जांच की मशीनों की मरम्मत का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि मशीनों में से कई मशीन एक संख्या में थे, जो वर्षों से ऐसी ही पड़ी हैं। मशीनों की खरीदी क्यों नहीं हो रही और खरीदी की प्रक्रिया क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि अस्पताल में 161 मशीन स्थापित हैं,

जिसमें से 50 मशीन बंद हैं, अभी 70 करोड़ की खरीदी कर रहे हैं 11 मशीनों का सुधार कार्य चल रहा है।

इसके बाद कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने पूछा कि कैंसर की जांच करने वाले मशीन क्यों नहीं है? इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं इलाज की श्रेणी में आती है। यह मशीन विदेश से आती है लेकिन हम उस मशीन को चालू भी करेंगे।

इसके बाद विधायक शेषराज ने पूछा कि यह मशीन पिछ्ले 9 साल पहले आपके ही कार्यकाल में खरीदी गई थी। 9 साल पहले खरीदी गई मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं कर पाए हैं? इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक अच्छे सोच के साथ मशीन की खरीदी की गई थी। कुछ कारणवश अगर चालू नहीं कर पाए हैं तो अभी करवा रहे हैं, लेकिन 5 साल आपकी भी सरकार थी।

अनाचार के आरोपी को मध्य प्रदेश से अकलतरा पुलिस पकड़ा

जांजगीर-चांपा नाबालिक बालिका से अनाचार के आरोपी को अकलतरा पुलिस ने मध्यप्रदेश से पकड़ा है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दिनांक 2 अप्रैल 25 को थाना अकलतरा मे अपराध क्रमांक 107/25 धारा 137 (2) BNS कायम कर विवेचना किया गया था। नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में सायबर तकनीकी के माध्यम से पता चला कि अपहृत बालिका आरोपी सचिन अहिरवार के कब्जे में जिला-विदिशा मध्यप्रदेश में है । उक्त सूचना पर थाना अकलतरा पुलिस द्वारा टीम रवाना कर आरोपी के कब्जे से अपहृत बालिका को सकुशल बरामद किया कर आरोपी को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपहृता बालिका को भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणिकात पाण्डेय थाना प्रभारी अकलतरा, सउनि अशोक कश्यप, महिला प्रधान आरक्षक रामकुमारी मार्को आरक्षक अजीत सिह राज का योगदान रहा।

सहकारिता को सशक्त बनाने सहकार भवन जांजगीर में आयोजित हुई महत्वपूर्ण कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत सहकार भवन जांजगीर में सहकारी योजनाओं, बायलॉज एवं साइबर सुरक्षा पर विशेष कार्यशाला आयोजित

जांजगीर-चांपा।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के वार्षिक कैलेंडर के तहत सहकारी जागरूकता व क्षमता संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सहकार भवन नोडल कार्यालय जांजगीर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले की समस्त प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधक, ऑपरेटर सहित बैंकिंग व सहकारिता विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सहायक पंजीयक सहकारिता श्री कामेश कश्यप, सहायक निदेशक एनसीडीसी रायपुर श्री सुभाष वर्मा, डीडीएम नाबार्ड जांजगीर श्री अंकित पाल, नोडल अधिकारी श्री अमित साहू एवं नोडल सहायक जीपी तिवारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री अमित साहू द्वारा अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित कर किया गया। अपने स्वागत वक्तव्य में श्री साहू ने सहकारिता क्षेत्र में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया तथा ऐसे आयोजनों को समय-समय पर आयोजित कर अधिकारियों एवं सहकारी समितियों से जुड़े कार्मिकों को

अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।

इसके पश्चात श्री सुभाष वर्मा, सहायक निदेशक एनसीडीसी रायपुर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एनसीडीसी किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफ्पीओ), प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में सहायक बन रही है। श्री वर्मा ने सहभागियों को केंद्र व राज्य स्तर पर संचालित नवीन योजनाओं से भी अवगत कराया।

इसके बाद नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री अंकित पाल ने नाबार्ड की योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन, महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में दी जा रही सहायता एवं ऋण योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने ब्रस्ट्स के माध्यम से गांव-गांव तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने पर बल दिया।

सहायक पंजीयक श्री कश्यप ने सहकारी समितियों की भूमिका, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए समितियों की पारदर्शिता, सही प्रबंधन एवं समय पर लेखा परीक्षण अत्यंत आवश्यक है।

कार्यशाला के अगले सत्र में नोडल सहायक जीपी तिवारी ने प्राथमिक सहकारी समितियों के बायलॉज पर विस्तारपूर्वक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। उन्होंने समितियों के गठन, उद्देश्य, कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व के विषय में सहभागी प्रबंधकों व ऑपरेटरों को जागरूक किया। श्री तिवारी ने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार बायलॉज के अनुरूप समितियों का संचालन सुचारु रूप से किया जा सकता है।

साथ ही उन्होंने वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर क्राइम एवं बैंकिंग फ्र ॉड के खतरों पर भी विस्तृत जानकारी दी। श्री तिवारी ने बताया कि डिजिटल लेनदेन के दौरान किन सावधानियों का पालन करना चाहिए एवं किस प्रकार साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। उन्होंने ह्ऊक्क पासवर्ड, फि शिंग कॉल, संदिग्ध लिंक आदि से जुड़ी सावधानियों पर भी चर्चा की।

कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जीपी तिवारी द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं अधिकारियों का सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया।

इस कार्यशाला से जिले की सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं ऑपरेटरों को योजनाओं की अद्यतन जानकारी, बायलॉज की बारीक समझ तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का अवसर प्राप्त हुआ। सहकारिता विभाग के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम से जिले की सहकारी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा समितियों के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

जिले में पहली बार डीएमएफसे 52 करोड़ से अधिक राशि से 481 नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

बाल शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में ठोस सुधार लाने हेतु जिला प्रशासन की बड़ी पहल

0 जिले के सुदूर और पहुँचविहीन क्षेत्रों में अब शिशु शिक्षा को मिलेगा नया आयाम

कोरबा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप जिले में बाल शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में ठोस सुधार लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ) का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा बड़ी पहल करते हुए कोरबा जिले के सुदूर और दुर्गम, पहुँचविहीन क्षेत्रों में 481 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 52 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पहल जिला प्रशासन की दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जिले में पहली बार डीएमएफसे 52 करोड़ 68 लाख 65 हजार की लागत से सभी विकासखंडों में कुल 481 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, इससे जिले में शिशु शिक्षा, पोषण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित ही नया आयाम मिलेगा। इस स्वीकृति के तहत कोरबा विकासखंड में 6 करोड़ 39 लाख 88 हजार की लागत से 56 नए आंगनबाड़ी भवन निर्मित किए जाएंगे। इसी प्रकार करतला विकासखंड में 8 करोड़ 63 लाख 85 हजार की लागत से 78 आंगनबाड़ी भवन, कटघोरा में 7 करोड़ 56 लाख 16 हजार की लागत से 65 आंगनबाड़ी भवन, विकासखंड पाली में 10 करोड़ 17 लाख 6 हजार की लागत से 93 आंगनबाड़ी भवन एवं पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड में 19 करोड़ 91 लाख 70 हजार की लागत से 189 आंगनबाड़ी भवन निर्माण किए जाएंगे । इन भवनों का निर्माण कार्य मे आवश्यक सुविधाओं को विशेष ध्यान रखा जाएगा जहाँ बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, पोषण आहार और स्वास्थ्य सेवाएं एक ही छत के नीचे सुलभ होंगी। इससे स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन भवनों के निर्माण से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बाल शिक्षा एवं पोषण सेवाओं को मजबूती मिलेगी साथ ही माताओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण भी सुनिश्चित होगा।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में भी शिशु शिक्षा को संबल प्रदान करने हेतु जिला खनिज न्यास निधि से जिले के नगरीय क्षेत्र के विभिन्न जोन के अनेक वार्डो में कुल 96 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 12 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिसमें नगर पालिका निगम कोरबा के विभिन्न जोन अंतर्गत 88 नए आंगनबाड़ी भवन एवं नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा के विभिन्न वार्डो में 08 नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य शामिल है। कलेक्टर द्वारा जिले के दूरस्थ क्षेत्रो, वनांचलों में बाल शिक्षा को मजबूती प्रदान करते हुए 52 करोड़ से अधिक राशि से 481 नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण से प्रारंभिक बाल विकास, पोषण सुधार और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नया बल मिलेगा। डीएमएफ राशि का यह सुनियोजित उपयोग जिले में शिशु शिक्षा और पोषण व्यवस्था को एक नई दिशा देगा।

खास खबर

महिला आईटीआई में विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए आनलाईन आवेदन 23 तक

कोरबा शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में संचालित व्यवसाय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, हिन्दी स्टेनोग्राफी स्युईंग टेक्नालाजी (कटिंग टेलरिंग) एनसीव्हीटी, एवं एससीव्हीटी स्युईग टेक्नालाजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी23 जुलाई 2025 तक आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक अपने स्तर अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से विभागीय वेबसाईटबहपजपण्बहेजंजमण्हवअण्पद पर जाकर आवेदन कर सकते है। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की इस वेबसाइट पर प्रवेश विवरणिका, सत्र 2025 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

रेडी टू ईट संचालन हेतु चयनित एवं प्रतिक्षा सूची में त्रुटि सुधार

कोरबा कोरबा जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना पसान अंतर्गत रेडी टू ईट संचालन के लिए समूहों से परियोजना पसान अंतर्गत दिनांक 19.05.2025 को जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह करीं एवं 20.05.2025 को मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त समूहों से प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पश्चात् समिति द्वारा अंतिम एवं प्रतिक्षारत् सूची तैयार कर मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा को चयनित एवं जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह को प्रतिक्षारत् किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया उपरोक्तानुसार चयनित पत्रक के नीचे टीप में छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महानदी भवन रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक एफ 3-55/2016/50(पार्ट) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.03.2025 के सरल क्रमांक 3.2 के निर्देशानुसार आदर्श महिला स्व सहायता समूह खिरटी को चयनित किया जाता है का लेख टंकण त्रुटिवश हो गया है जिसे सुधार कर आदर्श महिला स्व सहायता समूह खिरटीके स्थान पर मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह बैरा पढ़ा जावे।

डिजाइनर युवक की लाश मिली

बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के जूना बिलासपुर में दो दिन से गायब युवक की लाश मिली है. इसकी सूचना पर पुलिस ने एसडीआरएफ की सहायता से शव निकलवाकर पीएम के लिए भेज दिया है. पीएम की रिपोर्ट से युवक की मौत का कारण स्पष्ट होगा. कोतवाली थाना प्रभारी विवेक पांडेय ने बताया कि मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने पचरीघाट के पास नदी में एक युवक का शव देखकर पुलिस को सूचना दी. इस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. नदी के बहाव को देखते हुए पुलिस ने इसकी जानकारी एसडीआरएफ को दी. तब एसडीआरएफकी टीम भी मौके पर पहुंच गई. युवक की पहचान सीपत क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र उर्फराजू सूर्यवंशी (26) के रूप में हुई. स्वजन ने बताया कि राजेंद्र पोताई और दीवार पर डिजाइन बनाने का काम करता था. रविवार को वह अपने दोस्त कुश कुमार के साथ निकला था. उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी.

महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों को बैंक खाते से आधार लिंक कराना अनिवार्य

बिलासपुर जिले की महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जा रहा है। हितग्राहियों के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाता होना चाहिए। योजना प्रारंभ माह मार्च 2024 से माह मार्च 2025 तक कुल 13 माह का भुगतान हितग्राहियों को डीबीटी एवं एन.ई.एफटी दोनों माध्यमों से किया गया है। वर्तमान में माह अप्रैल 2025 से राज्य शासन द्वारा केवल डीबीटी के माध्यम से योजना अंतर्गत राशि का भुगतान किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। राज्य शासन द्वारा माह अप्रैल 2025 से केवल डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। तत्संबंध में आधार पंजीयन के 10 वर्ष होने पर आधार स्वतः इनेक्टीव हो जाता है, जिसके कारण आधार लिंक्ड बैंक खाता डीबीटी भी इनेक्टीव हो जाता है। ऐसे हितग्राहियों जिनका आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाता नहीं है अथवा आधार इनेक्टीव है उनका माह अप्रैल 2025 से योजना अंतर्गत भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त हितग्राहियों को दूरभाष के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर डीबीटी एवं आधार एक्टीव कराने की सूचना दी गई है एवं आधार एवं डीबीटी एक्टीव कराने हेतु सतत् रूप से हितग्राहियों को प्रेरित किया जा रहा है। कई ऐसे हितग्राही जो लोक सेवा केन्द्र एवं बैंक जाने में असमर्थ थे, उनको विभागीय कर्मचारियों द्वारा स्वयं लोक सेवा केन्द्र एवं बैंक ले जाकर आधार एवं डीबीटी एक्टीव खाता खुलवाया गया है। योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त होता है, को निर्देशानुसार प्राप्त पेंशन की राशि घटा कर (1000 /- रू. की राशि में से) शेष राशि का भुगतान किया जाता है।

जंगल से 15 जुआरी पकड़ में आये, 14 मोबाइल जप्त

कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाली थाना क्षेत्र के चैतुरगढ़ के निकट जंगल में जुआ का फड़ सजा है। कप्तान ने कटघोरा थाना प्रभारी निरीक्षक धर्म नारायण तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई करने का आदेश जारी किया और इसके साथ ही एक टीम ने सोमवार को दोपहर के वक्त जंगल में घेराबंदी की तो जुआ खेल रहे लोगों में अफरा- तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जानकारी के अनुसार मौके से लगभग 15 लोगों को पकड़ा गया। यहां से गिरफ्त में लिए गए कोरबा सहित पड़ोसी बिलासपुर जिला के जुआरियों से कुल 14 नग मोबाइल बरामद किए गए। 17 बाइक मौके से जप्त हुई है और बिलासपुर पासिंग की एक ब्रेजा कार क्रमांक सीजी 10 एई 0696 की भी जप्ती बनाई गई है। मौके से जुआ की रकम एक लाख से अधिक की जप्ती बनाई गई है। विस्तृत जानकारी संभवतरू मंगलवार को जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ नामचीन अड्डे जो शहर से लगे हुए जंगली इलाके में चल रहे हैं, वह गुलजार हैं। कप्तान की सख्ती और सीधे कप्तान से मुखबिरी के बाद कुछ मामले पकड़ में जरूर आ जाते हैं लेकिन कई मामले जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां अड्डे गुलजार हैं ।

स्टॉक रखे धान गायब, 54 लाख रुपए का गबन

बिलासपुर धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी और 54 लाख रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रिसदा धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कम्प्यूटर ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े के खिलाफस्न्नढ्ढक्र दर्ज कर लिया गया है। जिला सहकारी बैंक के मैनेजर ने मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, खरीफविपणन वर्ष 2024-25 में जिले के रिसदा धान खरीदी केंद्र से अनियमितता की शिकायत सामने आई थी। ऑनलाइन डेटा के अनुसार केंद्र में कुल 40879.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई। लेकिन भौतिक सत्यापन में धान खरीदी केंद्र में बड़ा शॉर्टेज मिला। 1763 क्विंटल धान कम पाया गया। जांच में पता चला कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े ने मिलकर इसमें गड़बड़ी की है और 54.67 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाते हुए पैसे का गबन कर लिया है।

ग्रामों के जारी नक्शा शीटों, खसरों पर दावा आपत्ति आमंत्रित

असर्वेक्षित ग्राम विश्रामपुर, कुटूरवां, अरसेना, व केरवां के नक्शा के अंतिम प्रकाशन हेतु उद्घोषणा जारी

भू-धारक कार्यालयीन समय में सबंधित ग्रामो के पंचायत भवन में नक्शा,खसरा का कर सकते है अवलोकन

व्यक्ति या संस्था 15 दिवस के भीतर दावा आपत्ति कर सकते हैं प्रस्तुत

कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन में जिला में असर्वेक्षित ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसके तहत राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील अजगरबहार अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 04 ग्राम विश्रामपुर, पटवारी हल्का नंबर 09 ग्राम कुटूरवां, पटवारी हल्का नंबर 09 ग्राम अरसेना एवं राजस्व निरीक्षक मंडल पसरखेत तहसील भैंसमा अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 11 ग्राम केरवां से प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने से अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही हेतु उद्घोषणा किया जाना है।

सर्वेक्षण कार्य एजेन्सी आईआईटी रुड़की द्वारा अंतिम प्रकाशन हेतु तहसील अजगबहार अंतर्गत ग्राम विश्रामपुर के 03 नक्शा शीट, कुटूरवां के 02 नक्शा शीट, ग्राम अरसेना के 04 नक्शा शीट एवं ग्राम केरवां के 02 नक्शा शीट उपलब्ध कराया गया है। संबंधित नक्शा शीटों का भौतिक सत्यापन राजस्व सर्वेक्षण दल द्वारा कराकर नक्शा व खसरा तैयार किया गया है।

हल्का पटवारी द्वारा तैयार अभिलेख खसरा व नक्शा भू-धारकों के अवलोकन हेतु संबंधित ग्रामों के पंचायत भवन में कार्यालयीन अवधि में उपलब्ध रहेगा। उक्त संबंध में हल्का पटवारी द्वारा तैयार किए गए नक्शा शीटों एवं खसरों पर दावा आपत्ति आमंत्रित है।

किसी भी व्यक्ति या संस्था को तैयार किए गए नक्शा शीटों पर आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से आगामी 15 दिवस के भीतर लिखित / मौखिक आवेदन कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से दावा आपत्ति संबंधित ग्राम पंचायत भवन में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

राशन दुकान संचालन में सरपंच पति की मनमानी

ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों की निजी और सामुदायिक समस्याएं इत्मीनान से सुनी और अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनदर्शन में आए किसानों से चर्चा कर खेती-किसानी के ताजा हालात और खाद-बीज की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल एवं एडीएम शिवकुमार बनर्जी ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।

साप्ताहिक जनदर्शन में सकरी तहसील के ग्राम देवरीकला के ग्रामीणों ने सरपंच पति के विरूद्ध राशन दुकान संचालन में मनमानी की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच रूपमणी सूर्यवंशी के पति शत्रुहन सूर्यवंशी के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन मनमाने तरीके से किया जा रहा है। वे राशन देने के लिए ग्रामीणों को अंगूठा लगाने घर आने बोलते है और यदि कोई नहीं आता है तो उसे राशन नहीं दिया जाता है। बिना किसी मुनादी के राशन का वितरण किया जाता है और वितरण के समय राशन 200-300 ग्राम कम दिया जाता है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य नियंत्रक को जांच के निर्देश दिए है। नगर पंचायत मल्हार की अध्यक्ष धनेश्वरी कैवर्त ने नगर पंचायत मल्हार में स्मार्ट मीटर लगने के बाद अधिक बिजली बिल आने की शिकायत की। इस मामले को विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता देखेंगे।

बेलतरा तहसील के ग्राम निपनिया के मुस्लिम समाज द्वारा समाज के लिए कब्रिस्तान हेतु जगह दिलाने आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने पत्र एसडीएम बिलासपुर को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सेमरताल निवासी दिलीप सूर्यवंशी ने आवास में रोजगार सहायक द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक ने दिलीप सूर्यवंशी के आवास का पैसा गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति के खाते में डाल दिया है, जिससे उनका घर अभी तक अधूरा है।

कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को जांच के निर्देश दिए है। कोटा ब्लॉक के ग्राम करहीकछार निवासी उर्मिला बैगा ने अपनी पुत्री निधि का आधार कार्ड बनवाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि पुत्री का चयन आदिवासी कन्या छात्रावास कोटा में हो गया है लेकिन आधार कार्ड नहीं होने के कारण प्रक्रिया बाधित हो रही है। कलेक्टर ने आवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को भेजा। रतनपुर तहसील के ग्राम सिंघरी निवासी महेंद्र साहू ने जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी 70 डिसमिल कृषि भूमि में से 20 डिसमिल पर दो लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। कलेक्टर ने इस मामले को एसडीएम को सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक माह की 9 एवं 24 तारीख को मनाया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस

कोरबा (आरएनएस)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान(पीएमएसएमए) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य हर महीने की 9 एवं 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं (दूसरी और तीसरी तिमाही में) की व्यापक एवं गुणवत्ता गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना है तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं फालोअप करना है जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। डॉ.एस.एन.केशरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर जब एक महिला गर्भवती होती है तो वह विभिन्न प्रकार की बिमारियों जैसे उच्च रक्तचाप,गर्भकालीन शुगर एनिमिया और हार्मोनल रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस (पीएमएसएमए) प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत समस्त शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में माह की प्रत्येक 9 एवं 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल सेवायें (जॉच और दवाओं सहित) प्रदान की जाती है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर उनके गर्भवस्था के दूसरी एवं तीसरी तिमाही की अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल सेवायें प्रदान किया जाता है तथा हर एक गर्भवती महिला की जॉच विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

कस्टम मिलिंग घोटाला : कोर्ट ने सात दिनों की और अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने मुख्य आरोपियों अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को कोर्ट ने सात दिनों की और अतिरक्त पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। दोनों आरोपियों को सोवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया गया था जहां से कोर्ट ने उन्हें 21 जुलाई 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले 9 जुलाई को दोनों को पहली बार पांच दिन की रिमांड पर लिया गया था। इस अवधि के दौरान की गई पूछताछ से मिली जानकारियों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11, 13(1)(क), 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली) एवं 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत केस दर्ज किया है।जानकारी मिली है कि रिमांड के अगले चरण में जांच एजेंसी अब उन आर्थिक नेटवर्कों और संदिग्ध लेन-देन की गहराई से जांच करेगी, जिनके जरिए करोड़ों रुपये का अवैध लाभ उठाया गया। इस दौरान और नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा पहले से ही शराब घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू की जांच के बाद उनकी भूमिका स्पष्ट होते ही इन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में होगा सुधार, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट से किया विधिवत शुभारंभ

रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में ई-ऑफिस प्रणाली का विधिवत शुभारंभ किया। डॉ. सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ज़िले के सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस एक अहम कदम है।

उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली से न केवल दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग और प्रसंस्करण आसान होगा, साथ ही इस पहल से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ समयबद्धता और दक्षता सुनिश्चित होगी, कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी और कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, ताकि इस प्रणाली का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। शासकीय कर्मचारी अपनी एनआईसी लॉगिन आईडी के माध्यम से वेबसाइट्स के जरिए ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य करेंगे।

बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री साय ने शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के बच्चों से की आत्मीय मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले की सुदूरवर्ती पाँच ग्राम पंचायतों के बच्चों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना और राजधानी रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी मूलभूत सुविधाएँ बस्तर के कोने-कोने तक पहुँचाने हेतु कृतसंकल्पित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हुए कहा कि इस शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से आपको राजधानी रायपुर को निकट से देखने-समझने का अवसर मिला है। इसी तरह राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र में भी तीव्र गति से विकास कर रही है। उन्होंने बताया कि सुदूर अंचलों में अब सुरक्षाबलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, और जहां-जहां ये कैंप पहुँचते हैं, वहाँ चौतरफा विकास के द्वार खुलते हैं। अब अधिकांश स्थानों पर शासकीय राशन दुकानों की स्थापना हो चुकी है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में बस्तर पूरी तरह से नक्सलमुक्त क्षेत्र होगा।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से मुस्कराते हुए पूछा – ÷बस्तर के शेर बच्चों ने रायपुर के जंगल सफारी में शेर देखा या नहीं?÷ इस मजाकिया अंदाज़ पर बच्चों सहित उपस्थित सभी लोग ठहाके लगाकर हँस पड़े।

श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। बस्तर के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें दुग्ध उत्पादन से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रही है, ताकि क्षेत्र के बच्चों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो सके।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायकगण श्री ईश्वर साहू एवं श्री सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत सुकमा जिले की पाँच सुदूर ग्राम पंचायतों–पालाचलमा, पोटकपल्ली, एलमागुंडा, ताड़मेटला एवं गोलापल्ली–के 100 स्कूली बच्चे राजधानी रायपुर के दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं। भ्रमण के दौरान इन बच्चों को मंत्रालय, जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कराया गया। विदित हो कि नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर के नक्सल प्रभावित पाँच जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

नवा रायपुर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री साय ने किया पौधारोपण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेते हुए गुलमोहर का पौधा रोपित किया। यह आयोजन 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृत्व के सम्मान को जोड़ना है।कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप सहित मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य और विधानसभा के सभी विधायक मौजूद थे। सभी ने सामूहिक रूप से गुलमोहर के पौधे लगाए और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव (वन) ऋचा शर्मा, वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय और मुख्य वन संरक्षक राजू अगासमणि ने भी पौधारोपण कर कार्यक्रम में सहभागिता निभाई।'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का यह दूसरा चरण है, जिसमें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ माताओं को श्रद्धांजलि देने का भाव जुड़ा हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के माध्यम से व्यापक जनभागीदारी हो और हर नागरिक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो।

नवा रायपुर में जैव विविधता और आर्द्रभूमि संरक्षण पर उच्चस्तरीय कार्यशाला आयोजित

रायपुर । जैव विविधता और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण को लेकर नवा रायपुर स्थित दण्डकारण्य अरण्य भवन में आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, राज्य के कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए केवल आधारभूत संरचना का विकास ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा भी आवश्यक है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से 'वेटलैण्ड मित्र' बनकर इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने की अपील की।वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वेटलैंड्स और जैव विविधता का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)